डाक पंजीयन सं. जयपुर सिटी/101/2020-22

वर्ष : 09 > अंक : 05 > मूल्य: 10 रुपए > पृष्ठ : 08

साप्ताहिक समाचार पत्र | मीडिया दृष्टिकोण

हिलव्यू समाचार

सफलता की कहानी कठिन रास्तों से होकर गुज़रती है।
- शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर, गुरुवार, 21 जुलाई, 2022

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746

hillviewsamachar@gmail.com

नहीं जाग रही राजस्थान सरकार

सरकारी संपत्ति 'रूपसिंह जी की हवेली', भी जयपुर कॉलेज के अतिक्रमणकारियों के कब्ज़े में

जयपुर कॉलेज में रूपसिंह जी की हवेली मर्ज होते हुए लाल गोले में।

अब गृह मंत्रालय भारत सरकार के संज्ञान में भी जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) चौड़ा रास्ता अवैध निर्माण

जयपुर कॉलेज अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर उषा शर्मा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कार्यवाही करने के निर्देश भी दे दिए हैं।

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर। जयपुर कॉलेज (नानाजी की हवेली,चौड़ा रास्ता) के बाद *रूपसिंह जी की हवेली भी होगी अब ज़मींदोज़। टूट कर बिख़रती जा रही वैश्विक धरोहर...

यह ख़बर हिलव्यू समाचार के 28 मार्च 2022 के अंक में प्रकाशित कर दी गयी थी कि रूपसिंह जी की हवेली जो कि सरकारी संपत्ति भी है और अभी पीडब्ल्यूडी के संरक्षण में है उसे भी जयपुर कॉलेज के अतिक्रमण में शामिल कर लिया जाएगा यानी जयपुर कॉलेज(नाना जी की हवेली) के अवैध निर्माण को चौड़ा रास्ता के मुख्य मार्ग की ओर से विस्तृत करने के लिए रूपसिंह जी की हवेली को भी हथिया लिया जाएगा ताकि मुख्य मार्ग पर अतिक्रमणकारियों को अवैध निर्माण का पूरा फ़ायदा मिल सके और जयपुर कॉलेज हवेली जो कि अब एक व्यवसायिक भवन में तब्दील हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू के साथ-साथ उसका सौंदर्यीकरण भी दुगुना हो सके। अब जयपुर कॉलेज के अतिक्रमी भूमाफ़ियाओं ने रूपसिंह जी की हवेली की छत पर अपना वर्चस्व जमा लिया है। छत से रूपसिंह जी की हवेली को जयपुर कॉलेज के निर्माण कार्य में शामिल करना प्रारम्भ हो चुका है। किराएदारों को डरा-धमकाकर भगाना जारी है और मंज़िल -दर-मंज़िल कब्ज़ा काबिज़ होता जा रहा है। सरकारी संपत्ति की चोरी को देखते हुए भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने आँखें क्यों मूंद रखी हैं यह किसी से छिपा नहीं।

शासन और प्रशासन दोनों के नाक के नीचे से सरकारी संपत्ति रूपसिंह जी की हवेली धीरे-धीरे सरक रही है और उसका अस्तित्व जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) में समाता जा रहा है।

कब इस अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलने की कार्यवाही शुरू होगी यह तो वक़्त बताएगा क्योंकि वर्तमान सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। कौन अपने दामन में आग लगाये। कहीं न कहीं पूरा का पूरा तंत्र राजधानी में कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे इन अवैध निर्माणों में लिप्त है किसी न किसी रूप में।

किसे ख़बर करें और कौन इस पर कार्यवाही करेगा यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब राजस्थान में तो किसी के पास नहीं।

ख़बर-बेख़बर

शालिनी श्रीवास्तव

स्टे लेना वाला स्वर्गवासी लेकिन स्टे आज भी ज़िंदा?

हिलव्यू समाचार

जयपुर। सीबीआई फाटक जगतपुरा के सामने जेडीए के 100 फिट रोड़ पर अवैध कब्ज़ा कर स्टे लेने वाले पूर्व आईपीएस हरिराम मीणा स्वर्गवासी हुए लेकिन उनके द्वारा लाया स्टे आज भी जिंदा है!

सीबीआई फाटक जगतपुरा जेडीए के 100 फिट रोड़ पर प्लॉट न.B-16 के मालिक पूर्व आईपीएस हरिराम मीणा ने चबूतरा बनाकर कब्ज़ा किया। जेडीए की कार्यवाही पर वे स्टे ले आये। इस कब्ज़े को कई साल हो गए। छह माह पूर्व हरिराम मीणा स्वर्ग सिधार गए लेकिन जेडीए ने अब तक भी इस स्टे को खारिज़ करवाने की कार्यवाही शुरू नहीं की।

पवन विहार कॉलोनी, जगतपुरा के सामने इस मुख्य मार्ग पर यातायात बहुत अधिक रहता है। बड़े-बड़े साधन यहाँ से गुज़रते हैं। आम साधन व पैदल आम आदमी इस अवैध निर्माण के चलते बेहद सतर्कता से यहाँ से गुज़र पाते हैं। यातायात तो बाधित हो ही रहा है और इसके अतिरिक्त 100 फिट रोड़ के सिमटने से आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी प्रभावित हो रहा है।

निरन्तर भारी यातायात का आवागमन (ऊपर) एवं कब्ज़े का चबूतरा (नीचे)।

जयपुर विकास प्राधिकरण अब किस इंतज़ार में है ?

या यूँ कहें कि सरकारी संपत्ति व सौंदर्य को लेकर जागरूक क्यों नहीं जेडीए ?

साइबर क्राइम पर अब सख़्त क़दम उठाये सरकार...

शॉर्टकट और कुछ मिनटों में अमीर बनने का सपना, बहुत महंगा सौदा...

हिलव्यू समाचार

जयपुर। लगातार शॉर्टकट से सफल होने या अमीर बनने का शोर आजकल की युवा पीढ़ी की सोचने समझने की शक्ति छीन रहा है। कम समय में अधिक पाने की चाहत को हवा देते हैं ये ऑनलाइन गेम्स,एप और साइट्स।

गत वर्षों में अकाउंट हैक करना,मोबाइल या आपकी कोई भी सोशल साइट्स हैक करना साइबर चोरों के बाँयें हाथ का खेल बन गया है।

इन दिनों एक नया तरीका और खोज निकाला गया है बच्चों,युवा पीढ़ी व घरेलू महिलाओं व नासमझ लोगों को लूटने का। कुछ घण्टों में अमीर बना देने वाले एप मार्केट में उसी तरह चिल्ला रहे हैं जैसे मेले या बाज़ार में खड़े दुकानदार ग्राहक को आवाज़ देकर अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसी तरह जैसे ऑटो टेम्पो वाले बाज़ार, रेलवे स्टेशन,बस स्टैंड से निकलते लोगों पर लपकते हैं। यहाँ तक कि ये कमर्शियल साधन वाले स्कूल कॉलेज परिसर से निकलते हुए बच्चों को अपने वाहन में बैठाने के लिए घेर लेते हैं और हर कोई अपने साधन में उन्हें बैठाने को पुरज़ोर कोशिश कर रहा होता है। बस यही तरीक़ा इन फ्रॉड एप्स का है जो आजकल के युवा वर्ग,महिलाओं व बच्चों को लुभावने विज्ञापन देकर अपनी ओर खींच रहे हैं जैसे--

'है जीत की तलब और जीत लेगा सब!'

ये है जलवा जुण्णी का! डाउनलोड करें जल्द.....

'मैच के बाद हाईलाइट्स भी ....तो क्रिकेट का भूत आप पर भी सवार है!' प्लेयरज़पोट डाउलोड करें जल्द.....

गाईज़!! बिग कैश app पर कितने सारे गेम्स हैं, मुझे तो पता है मेरा टाइम कहाँ जाने वाला है ??

डाउनलोड करो और जम कर खेलो बिगकैश app पर !!!

गौर करने वाली बात यह है कि इन एप्स को प्रसारित करने वाले सारे अभिनय कर्ता युवा लड़के-लड़कियाँ हैं जो टीवी सीरियल या वेब्सिरीज़ के कलाकार हैं। उनका बनावटी उत्साह आज की युवा पीढ़ी को अंधकार की ओर धकेल रहा है।

आप यूट्यूब, डिज़्नी हॉट स्टार, वूट, नेटफ्लिक्स पर कोई भी मूवी, सीरियल, गेम चलाइये इनमें एड भरे पड़े हैं जो पलभर में अमीर बना रहे हैं! पल भर में आकाश में उड़ा रहे हैं। आवश्यकता से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहे हैं।

बिग कैश एप, प्लेयरज़पोट, जुप्पी, जुआ खेल, पबजी जैसे एप्स और भी कई ऑनलाइन एप हर चीज़ को जल्द पाने की चाह पनपा रहे हैं ये एप और सोशल मीडिया का अति प्रयोग हमारी पीढ़ी को गर्त में ले जा रहा है !

इन पर सरकार सख़्ती से रोक लगाए। ऑफ लाइन सट्टे पर रोक है तो इस ऑनलाइन सट्टे को तो ज़्यादा सख़्ती से बन्द होने की आवश्यकता है।

पीड़ित अमित शर्मा, जयपुर

कुछ दिन पूर्व एक एप से मेरे पास मैसेज आया कि अपनी राशि को दोगुना करें पैसा लगाएँ और दुगुना पाएँ। मैंने दिए गए लिंक को डाउनलोड किया। टेलीग्राम के माध्यम से मेरी चैट (बातचीत) शुरू हुई। शुरू मैंने परीक्षण के लिए 100 रुपये लगाए 200 आ गए तुरंत। 1000 लगाए 2000 हज़ार आ गए। सिलसिला 8000 तक पहुँच गया फिर 28000 तक। उसके बाद अकाउंट फ्रीज हुआ उन साइबर फ़र्ज़ीयों की ओर से।अधिक राशि लगाने को वे मुझे राजी करते रहे और डूबी हुई राशि को निकालने के लिए मैं राशि लगाता चला गया आख़िर दो लाख तक लगा चुकने के बाद मुझे अहसास हुआ कि मैं शिकार हो गया साइबर गेम्स की डकैती का। उसके बाद मैंने चैटिंग पर मेरे पैसे लौटने की बात की लेकिन दूसरी तरफ़ से आज तक कोई संपर्क नहीं न ही कोई मैसेज है।

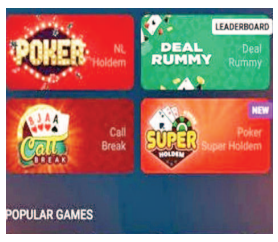

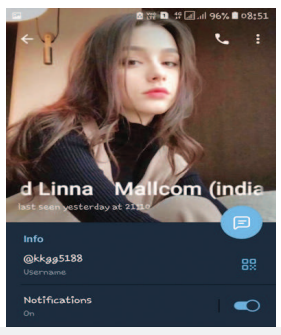

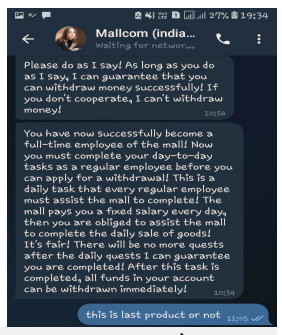

ये लुभाने वाली एप्स या साइट्स उसमें चाहे गेम्स हों या कोई पैसा दुगुना करने की सट्टा स्कीम,ये कभी भी आपको सफलता या शॉर्टकट से लाखों रुपया नहीं दिला सकती।बल्कि लूट लिए जाने के बाद मानसिक, शारीरिक परेशानी का सबब तो ये बनती ही है बल्कि आपको हास्य का पात्र भी बना देती है।अतः इस तरह के बिग कैशएप,प्लेयरज़पोट,जुप्पी,जुआ खेल,पबजी,लूडो,कार्ड्स कोई गेम्स या एप्प का सदस्य बनने से बचें और लोगों को,मित्रों को,रिश्तेदारों को,साथियों, सहयोगियों, पड़ौसियों भी सतर्क करें। यह लुभावने विज्ञापन आपके करिअर ही नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए भी घातक सिद्ध हो सकते हैं।

30 जुलाई को सुबह 6 बजे जवाहरकला केंद्र से गाँधी सर्कल तक होगी दिव्यांगजन मैराथन दौड़

सृष्टि द वुमन्स क्लब की अनूठी पहल देगी हौसलों को उड़ान

हिलव्यू समाचार

जयपुर। सृष्टि द वुमन्स क्लब की ओर से दिव्यांगजन मैराथन दौड़ 'हौसलों की उड़ान' का अनूठा आयोजन 30 जुलाई को होगा। इसमें 100 से ज़्यादा दिव्यांगजन भाग लेंगे। सृष्टि क्लब की अध्यक्ष मधु सोनी ने बताया कि यह दिव्यांगजन मैराथन दौड़ जवाहर कला केंद्र के मुख्य द्वार से प्रारम्भ होकर गाँधी सर्कल का राउंड करेगी। इस दौरान सुबह 6 बजे से 8.30 बजे तक इस मार्ग का यातायात अन्य मार्गों पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। तत्पश्चात जवाहरकला केंद्र के रंगायन सभागार में यह दिव्यांगजन सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगे जिसमें दौड़ में प्रथम,द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को पुरुस्कार दिए जाएंगे। बेस्ट ट्राय साइकल डेकोरेशन सहित कई इनाम दिए जायेंगे। प्रत्येक दिव्यांगजन प्रतिभागी को स्पेशल किट सामग्री सहित भेंट स्वरूप दी जाएगी। जिसके पास ट्राय साइकल नहीं है उन्हें वह दी जाएगी। गत सप्ताह इस कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन सुनीता मीणा डीसीपी, डीसीपी ईस्ट डॉ राजीव पचार, राजलक्ष्मी डिप्टी गोपालपुरा थाना, महावीर टेलर, सोहित टेलर रेनु खुराना, सुनीता सोनी, अवधेश, कमलेश सोनी पंजाब नेशनल बैंककर्मी मोहित शर्मा, हेमंत भाई गोयल, महावीर कुमार सोनी, राज शर्मा, कुलदीप गुप्ता, संजीव,सपना पाठक, नरेंद्र कुमार जैन, राजेंद्र शर्मा, बसंत जैन एवं सृष्टि क्लब सदस्यों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया।

संपादकीय

शिक्षण को महत्व देने का समय, ताकि टापर्स भी बनना चाहें शिक्षक

एक युवा छात्र ने पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा था- 'सर, आपको जीवन में महान चीजों को हासिल करने की प्रेरणा कैसे मिली?' डा. कलाम ने उत्तर दिया, 'मैं जब पांचवीं कक्षा में था तब प्राथमिक विद्यालय के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर से मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन फैसला किया कि मैं उन मशीनों के साथ काम करूंगा, जो उड़ सकती हैं।' कुछ वर्षों बाद युवा कलाम ने भारत को अपने लड़ाकू विमानों, उपग्रहों और मिसाइलों को हवा और अंतरिक्ष में उड़ाने की क्षमता प्रदान दी।

वास्तव में शिक्षक समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। वे सामाजिक मनोबल और भविष्य के नेताओं का निर्माण करते हैं। हमारे देश में लगभग 97 लाख शिक्षक हैं, जिनकी तैनाती 15 लाख स्कूलों में है। इनमें से दो तिहाई से अधिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं, जो अक्सर आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में ज्ञान की उम्मीद जगाते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत में एक लाख से अधिक स्कूल सिर्फ एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में हैं। भारत की शिक्षा के यही नायक देश के उन 25 करोड़ बच्चों का भविष्य लिखते हैं, जो इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। विकास के इन स्तंभों की बेहतरी, गुणवत्ता, प्रेरणा और सुधार एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?

सबसे पहला मुद्दा गुणवत्ता का है। हर बार सर्वेक्षणों से यही सामने आता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की शिक्षा गुणवत्ता के पैमाने पर बहुत नीचे है। यह एक ऐसे राष्ट्र के लिए चिंताजनक है, जो अपने युवाओं पर गर्व करता है।

शिक्षण की स्थिति में सुधार के लिए हमें शिक्षकों की स्थिति में सुधार करना होगा। इसके लिए हमें शिक्षकों को चुनने और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बनाए रखने के तरीके को बदलने की जरूरत है। हमें बीएड और एमएड जैसे प्रोग्राम में सुधार करने की जरूरत है, जो अब पुराने और अप्रासंगिक हो गए हैं। चूंकि इन डिग्रियों को हासिल कर ही अधिकांश शिक्षक तैयार होते हैं, इसलिए इनमें पढ़ाने और सीखने के मनोविज्ञान में आधुनिक तरीकों को शामिल करने की आवश्यकता है।

शिक्षक अपनी गुणवत्ता को परखें, इसके लिए देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों और संस्थानों के साथ साझेदारी में उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरने का समय दिया जाना चाहिए। इसरो, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, मेट्रो रेल जैसे संगठनों और अन्य हाइटेक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे स्कूली शिक्षकों को अत्याधुनिक तकनीक के विषय में प्रशिक्षित करें। शिक्षकों की वेतन वृद्धि को हर पांच साल में किए जाने वाले इस तरह के आकलन से जोड़ा जाना चाहिए। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को तेजी से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें मध्यम स्तर पर शिक्षकों के पदों पर लैटरल इंट्री दी जानी चाहिए। दूसरा पहलू फोकस का है। शिक्षक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उनका इस्तेमाल चुनाव ड्यूटी, जनगणना और टीकाकरण के लिए अतिरिक्त कार्यबल के रूप में नहीं किया जा सकता है। मुख्य भूमिका से हटाकर उन्हें इस तरह से दूसरे कामों में लगाना यह दिखाता है कि एक शिक्षक के काम को हम कितना सम्मान देते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की जगह कोई और नहीं ले सकता है। कक्षा की अपनी ही एक गरिमा होती है। इसकी गरिमा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

तीसरा मसला विकास का है। एक शिक्षिका 20 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करती है। लगभग चार दशकों की नौकरी में वह 50 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा किसी स्कूल की प्रिंसिपल बनने की उम्मीद कर सकती है। उस उम्र और अनुभव के बाद भी उस शिक्षक पर नई नियुक्ति पर आए एक नौकरशाह का हुक्म चल सकता है, जो खुद कभी शिक्षक की भूमिका में नहीं रहा होगा। शिक्षा नीति के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका न के बराबर होती है। हमें शिक्षा के क्षेत्र को शिक्षकों को सौंपने पर विचार करना चाहिए। स्कूल विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों को विशेष रूप से पूर्व शिक्षकों को दे दिया जाना चाहिए। उन्हें यह तय करने देना चाहिए कि स्कूलों के लिए सबसे अच्छा क्या है।

अंत में काम के माहौल का मुद्दा है। किसी भी अन्य पेशेवर की तरह ही शिक्षक भी अपने काम की जगह पर सम्मान के हकदार हैं। दूरदराज के स्कूलों में परिवहन के लिए भत्ता, एक अच्छी तरह सुसज्जित स्टाफ रूम, शिक्षकों के लिए एक अच्छा शौचालय बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं। अधिकांश स्कूलों में अक्सर इनकी कमी देखी जाती है। किसी भी वयस्क पेशेवर से इन सभी मुश्किलों को सह कर भी प्रेरित रहने की उम्मीद करना सच से परे है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं।

शिक्षक की भूमिका किताबों को पढ़ाने भर से कहीं बड़ी है। शिक्षक एक मिसाल होता है जिसे बच्चे देखते हैं और उसके पदचिह्नों पर चलते हैं। वे न केवल भविष्य के कौशल का निर्माण करते हैं, बल्कि राष्ट्र के मूल्यों को भी आकार देते हैं। इसलिए हमारे युवाओं के बीच शिक्षण को पसंदीदा पेशा बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। किसी क्लास के टापर्स को इंजीनियर, डाक्टर और सिविल सेवकों के अलावा महान शिक्षक बनने की इच्छा भी रखनी चाहिए।

सुरक्षित करिअर ग्रीन सेक्टर

पिछले कई दशकों से हमारी पृथ्वी गंभीर एनवायरनमेंटल चुनौतियों से जूझ रही है और दुनिया भर के देश अब क्लाइमेट चेंज को रोकने के साथ ही अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं. भारत सहित दुनिया के सभी देश एनवायरनमेंट अर्थात ग्रीन सेक्टर से संबंधित कार्यों में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और इस वजह से आजकल इस फील्ड में यंगस्टर्स और पेशेवरों के लिए सुरक्षित करिअर शुरू करने के कई अवसर रोजाना उपलब्ध हो रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों से भारत में हर साल 8000 से 10,000 ग्रीन सेक्टर जॉब्स के लिए भर्ती हो रही है. वर्ष 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग्स तैयार करने के लिए 1 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी और रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में वर्ष 2030 तक 1.4 करोड़ पेशेवर रोजगार से जुड़े होंगे.

भारत में अवसर

- **एग्रीकल्चर एक्सपर्ट**
ये पेशेवर हमारे देश में फसलों के उत्पादन और एग्रीकल्चर से संबंधित सभी कार्य, जैसे मिट्टी का संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और पशुपालन आदि संभालते हैं.
- **एनवायरनमेंट एक्सपर्ट**
देश-दुनिया में ये पेशेवर नेचुरल एनवायरनमेंट को कायम रखने के लिए इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज अपनाने के साथ पोल्यूशन कंट्रोल के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.
- **एनर्जी इंजीनियर**
आजकल पूरी दुनिया सहित भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है और ये पेशेवर इस फील्ड में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.
- **रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट**
ये पेशेवर प्रमुख रूप से विभिन्न कंपनियों, उद्योगों और दफ्तरों में रोजाना होने वाले कामकाज तथा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि से जुड़े रिस्क या खतरों से कंपनी व कर्मचारियों की सुरक्षा करते हैं.
- **कंजरवेशनिस्ट**
ये पेशेवर मुख्य रूप से वाटर कंजर्वेशन का कार्य करते हैं और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.
- **प्रोडक्शन हेड/ मैनेजर**
इन पेशेवरों का प्रमुख काम विभिन्न उद्योगों में होने वाले प्रोडक्शन को एनवायरनमेंट के अनुकूल अर्थात इको-फ्रेंडली बनाना है.
- **ग्रीन आर्किटेक्ट**
इन पेशेवरों का प्रमुख कार्य ग्रीन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सभी बिल्डिंग्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाना होता है.

अन्य जॉब प्रोफाइल्स

- रिसर्चर
- फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ मैनेजर
- लैब टेक्नीशियन
- नेचर कंजरवेशन ऑफिसर
- रीसाइक्लिंग ऑफिसर
- वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर
- प्लांट ऑपरेटर
- हाइड्रोलॉजिस्ट

टॉप इंस्टीट्यूट्स

- दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
- जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
- टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, नई दिल्ली
- इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बेंगलुरू
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई/ खड़गपुर
- वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उत्तरांचल
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ/ मुंबई/ खड़गपुर/ दिल्ली/ रुड़की/ कोलकाता/ बेंगलुरू

प्रमुख एजुकेशनल कोर्सेज →

ग्रीन सेक्टर या एनवायरनमेंट की फील्ड से संबंधित कोई एजुकेशनल कोर्स करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त एजुकेशनल बोर्ड से आपने 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम में पास की हो.

- **बीएससी/ बीई/ बीटेक - एनवायरनमेंटल साइंस -** स्टूडेंट्स ने किसी मान्यताप्राप्त एजुकेशनल बोर्ड से अपनी 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम में पास की हो. इन कोर्सेज की अवधि 3 वर्ष है. इसी तरह, इस फील्ड में सर्टिफिकेट कोर्सेज की अवधि 6 महीने से 1 वर्ष तक हो सकती है.
- **एमएससी/ एमई/ एमटेक - एनवायरनमेंटल साइंस -** स्टूडेंट्स ने किसी मान्यताप्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो. इन कोर्सेज की अवधि 2 वर्ष है.
- **एमफिल– एनवायरनमेंटल साइंस –** स्टूडेंट्स के पास किसी मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से साइंस की स्ट्रीम में पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री हो. इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष है.
- **पीएचडी– एनवायरनमेंटल साइंस –** स्टूडेंट्स के पास एमएससी या एमफिल की डिग्री हो. इस कोर्स की अवधि 3- 5 वर्ष है.

आर्ट्स में विकल्पों की भरमार

आर्ट्स से 12वीं करने के बाद स्टूडेंट्स के पास हॉस्पिटैलिटी, लॉ, ट्रैवल, मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में काम करने और करिअर बनाने का मौका होता है. स्टूडेंट्स अपने इंट्रेस्ट के मुताबिक इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. जानिए, आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं के बाद किन-किन सेक्टर में करिअर बनाने का विकल्प होता है.

बैचलर ऑफ डिजाइन (एनिमेशन)

आर्ट्स से 10+2 करने के बाद स्टूडेंट्स के पास एनिमेशन में बैचलर ऑफ डिजाइन करने का विकल्प रहता है. अगर आपका इंट्रेस्ट कुछ अपना क्रिएटिव तैयार करने, डिजाइन करने और एनिमेशन में है तो इसे किया जा सकता है. एनिमेशन में कई कैटेगरी मिलती हैं, जिन्हें आप अपने इंट्रेस्ट और सुविधा के मुताबिक चुन सकते हैं. जैसे- 2डी/3डी एनिमेशन, एनिमेशन फिल्म मेकिंग और वेब डिजाइन आदि. एनिमेशन के अलावा भी बैचलर ऑफ डिजाइन के तहत स्टूडेंट्स को कई विकल्प मिलते हैं जो उनके भविष्य के लिहाज से बेहतर होते हैं. जैसे- फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन आदि. NIFT, NID और UCEED जैसे एंट्रेंस एग्जाम के जरिए इन कोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है.

बीए-एलएलबी

हर साल बीए-एलएलबी के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कराए जाते हैं, इसमें सफल होकर एडमिशन पा सकते हैं. आर्ट्स के बाद बीए-एलएलबी का 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने का विकल्प भी रहता है. अगर आप लॉ के क्षेत्र में करिअर बनाने के लिए इंट्रेस्टेड हैं तो यह बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. देश के ज्यादातर बड़े शहरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में यह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाता है. कैंडिडेट चाहें तो क्रिमिनल लॉ या कॉन्सटीट्यूशनल लॉ में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं. इसके लिए CLAT, AILET, LSAT India जैसे एंट्रेस एग्जाम के जरिए प्रवेश पा सकते हैं. बीए-एलएलबी प्रोग्राम दूसरे एलएलबी प्रोग्राम से अलग होता है. यह बीए और एलएलबी का कॉम्बिनेशन होता है. यह प्रोग्राम 2 कोर्सेस को कम्बाइंड करके तैयार किया गया है.

बीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल

अगर आपको घूमने और घुमाने का शौक है, नई जगहों के बारे में जानकारी रखते हैं तो ट्रैवल से बीए कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई भी कराई जाती है. इसलिए इस प्रोग्राम के तहत एक स्टूडेंट के पास हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कुलीनरी आर्ट्स, फेयर एंड टिकटिंग में स्पेशलाइजेशन का विकल्प रहता है. IIHM और eCHAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम के जरिए इस कोर्स में एंट्री पा सकते हैं.

डिप्लोमा इन एजुकेशन

डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड एक अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है. अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए खुद को फिट मानते हैं तो डीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. डीएड करके आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मौके पा सकते हैं. ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में डीएड क्वालिफाइड टीचर की मांग होती है.

बीसीए (आईटी एंड सॉफ्टवेयर)

अगर आपको तकनीक से जुड़ी चीजें आकर्षित करती हैं तो बीसीए किया जा सकता है. देश में कई ऐसे कॉलेज हैं जो बीसीए के लिए 12 में मैथ्स को अनिवार्य मानते हैं. वहीं, कुछ ऐसे संस्थान हैं, जहां बीसीए करने के लिए 12वीं में मैथ्स का होना अनिवार्य नहीं है. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरू, सिक्किम मनिपाल यूनिवर्सिटी और सेंट जेवियर्स कॉलेज, जयपुर समेत कई संस्थानों में मैथ्स को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं मांगा जाता.

ऐसे करें इंग्लिश इम्प्रूव

बातचीत को रिकॉर्ड करें

अंग्रेजी पढ़ें या बातचीत करें, इसे रिकॉर्ड जरूर करें. रिकॉर्डिंग के बाद इसे सुनें. इस तरह आप यह समझ पाएंगे कि आपकी आवाज दूसरों को कैसी सुनाई देती है, उसका एक्सेंट कैसा है, उच्चारण को कितना बेहतर बनाने की जरूरत है. इसलिए अपनी रिकॉर्डिंग जरूर सुनें.

सही समय चुनें

सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, किसी भी भाषा को सुनने के लिए ऐसा समय चुनें, जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएं, ज्यादा मन लगा पाएं और डिस्टर्बेंस कम से कम हो. सिर्फ किसी भाषा को सीखना ही जरूरी नहीं होता, उसे हमेशा के लिए समझना जरूरी है.

म्यूजिक सुनें

इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादातर कैंडिडेट अंग्रेजी मूवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ अंग्रेजी गाने भी सुनें. खासकर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट वाले. इससे आप उस भाषा को बेहतर समझ पाते हैं और दोनों लैंग्वेज के फर्क को भी जान पाने में समर्थ हो जाते हैं.

माता-पिता की सलाह ने बदली लाइफ

Success Story

इंजीनियरिंग छोड़ बनीं IAS अफसर

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस एग्जाम में हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं, लेकिन कुछ को ही सफलता मिलती है. हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी एक सलाह से बदल जाती है. ऐसी ही कुछ कहानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली तेजस्वी राणा की है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के बाद माता-पिता की सलाह पर यूपीएससी में जाने का फैसला किया और दूसरे प्रयास में आईएएस अफसर बनने में सफल रहीं.

आईआईटी कानपुर से ली डिग्री

हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने तेजस्वी बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थीं और उन्होंने 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा भी अच्छे नंबरों से पास की. 12वीं के बाद तेजस्वी ने जेईई परीक्षा दी और इसमें भी सफल रहीं. इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की.

UPSC में जाने का फैसला

इंजीनियरिंग के दौरान तेजस्वी का आकर्षण सिविल सर्विस की तरफ हुआ और उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देने का मन बना लिया था. हालांकि उनके लिए इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी में जाने का फैसला करना आसान नहीं था. इसके बाद उनके माता-पिता ने उनकी मदद की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद माता-पिता की सलाह पर यूपीएससी में जाने का फैसला किया.

पहले प्रयास में हो गईं फेल

तेजस्वी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करते ही यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में जुट गईं और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने साल 2015 में पहली बार एग्जाम दिया, लेकिन वह फेल हो गईं. तेजस्वी अपने पहले प्रयास में प्रिलिम्स परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन वह मेन्स परीक्षा नहीं पास कर पाईं.

हासिल की 12वीं रैंक

पहले प्रयास में हुई गलतियों को पहचानकर तेजस्वी ने उसमें सुधार किया और दूसरी बार परीक्षा देने का फैसला किया. सही रणनीति और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने साल 2016 में यूपीएससी परीक्षा पास की और ऑल इंडिया में 12वीं रैंक हासिल कर आईएएस अफसर बनने में सफल रहीं.

NCERT बुक्स से करें तैयारी

तेजस्वी का मानना है कि सिविल सर्विसेस की तैयारी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की क्लास 6 से 12 तक की किताबें इकट्ठा करें और बेसिक्स मजबूत करने पर जुट जाएं. एनसीईआरटी की किताबों से सबसे पहले बेसिक्स मजबूत करें और फिर स्टैंडर्ड बुक्स के साथ तैयारी करें.

बड़े काम का इंटर्नशिप अनुभव

जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त सीवी में अक्सर कैंडिडेट इंटर्नशिप की जानकारी तो देते हैं, लेकिन उसे बहुत कमतर आंकते हैं. यही वजह है कि इसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस में नीचे की तरफ लिखते हैं. ऐसा करना एक गलती की तरह है क्योंकि इंटर्नशिप का अनुभव किसी भी कैंडिडेट के लिए करिअर की नींव होता है. जानिए, सीवी में इंटर्नशिप के अनुभव को कैसे पेश करें...

प्रॉपर जिक्र करें

सीवी में इंटर्नशिप के अनुभव को बताते हुए ध्यान रखें कि आपने उस दौरान जो भी काम किया है, वह सब कुछ 2 से 4 लाइन में अच्छी तरह से समझाएं. सीवी में इंटर्नशिप बताने का सीधा असर एम्प्लॉयर पर पड़ता है. वह यह समझ पाता है कि कैंडिडेट जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है, उसे उसकी बेसिक जानकारी पहले से है.

ये बातें ध्यान रखें

- सीवी में इंटर्नशिप का अनुभव कभी एकेडमिक सेक्शन में न लिखें. इसे वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में हाईलाइट करते हुए लिखना बेहतर है.
- अगर आपने एक से अधिक इंटर्नशिप की हैं तो सीवी में इंटर्नशिप का एक सेक्शन बनाएं और इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंटर्नशिप की जानकारी दें.
- इंटर्नशिप के बारे में लिखने के दौरान अपने संस्थान का नाम, कितने महीने वहां काम किया, लोकेशन, पोजिशन और इस दौरान आपकी जिम्मेदारियां क्या थीं, ऐसी सभी जानकारियों को पॉइंटर में लिखें.

एडमिशन ALERT

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरू, कर्नाटक

कोर्स	एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (ईपीजीपी)
योग्यता	न्यूनतम 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है.
कार्य अनुभव	न्यूनतम 5 वर्ष
चयन प्रक्रिया	इंटरव्यू
आवेदन की अंतिम तारीख	22 अगस्त, 2022
इंटरव्यू की तारीख	10-11 सितंबर, 2022

हिलव्यू समाचार

hillviewsamachar@gmail.com

जयपुर, गुरुवार, 21 जुलाई, 2022

मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बोले... हम कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं: कहा...

धारीवाल का अलाइनमेंट गड़बड़ है, हम कांग्रेस में सेट नहीं होते हैं!

हिलव्यू समाचार

जयपुर। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अब कांग्रेस और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। गुढ़ा ने कहा- हम लोग कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई भी है। इसको बचाया भी है, लेकिन हम कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस का कल्चर पता नहीं क्या है, लेकिन हम हमारे हिसाब से आते हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं हम किस मूड के आदमी हैं, बाकी का पता नहीं वह कैसे जाते हैं। राजेंद्र गुढ़ा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

गुढ़ा ने कहा- कांग्रेस का कल्चर समझ नहीं आता। हम हाथों-हाथ लोगों के काम करते हैं। हमारा तो यही है कि रोज जब जनसुनवाई करते हैं तो 500 से 1000 लोग आते हैं, यह रूटीन का काम है।

PCC में मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं अकेला अपने क्षेत्र में हजार पांच सौ लोगों की जनसुनवाई करता हूँ और यहां पर बहुत कम लोग हैं। प्रदेश कांग्रेस में अगर लोगों की समस्याओं का समाधान हो तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, इसका रिजल्ट शानदार आएगा।

धारीवाल का अलाइनमेंट गड़बड़ है: गुढ़ा ने कहा- हमारे काम हो रहे हैं, थोड़े बहुत अटक रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ है, वह ठीक कर देंगे। दिल्ली तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत जो अलाइनमेंट गड़बड़ है उसको ठीक करेंगे। अलाइनमेंट थोड़ा सा शांति धारीवाल का गड़बड़ है। उसको ठीक करेंगे। धारीवाल के अलावा कोई मंत्री ऐसा नहीं है, जिसका अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ है।

अफसरों को कसकर रखें: गुढ़ा ने कहा- यह मेरा सुझाव है कि सरकार है तो अधिकारियों पर लगाम खींच कर रखनी चाहिए। हम लोग तो मजबूत सवार है। लोगों का हाथों-हाथ काम होना चाहिए। अफसरों को टाइम बाउंड करें, उन्हें कसें। वह IAS हो या IPS,तुरंत काम हो। रिक्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा।

गुढ़ा के बयाने के सियासी मायने: राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस की कल्चर में सेट नहीं होने का बयान देकर आने वाले समय के लिए सियासी संकेत दे दिए हैं। गुढ़ा ने सरकार और पार्टी के कामकाज की शैली पर सवाल उठाकर सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

पिछली कांग्रेस के सरकार के वक्त में भी गुढ़ा सहित छह बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। बाद में वे कांग्रेस के टिकट पर हार गए तो पार्टी छोड़ दी। पिछला चुनाव बसपा से लड़ा और जीतने के बाद कांग्रेस में विलय कर दिया। सियासी जानकारों के मुताबिक गुढ़ा ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे आगे भी सियासी जरूरत के हिसाब से पुरानी पार्टी में जा सकते हैं।

शिक्षा विभाग की आधी-अधूरी तैयारी: 214 अंग्रेजी स्कूलों का सत्र शुरू, लेकिन पढ़ाएगा कौन, अभी तक यह ही तय नहीं

हिलव्यू समाचार

जयपुर। प्रदेश में अब तक 1206 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले जा चुके हैं लेकिन इसी सत्र से खुले 214 अंग्रेजी स्कूलों में कौन पढ़ाएगा, अभी तक तय नहीं है। इन स्कूलों में निशुल्क किताबें भी नहीं पहुंची हैं। जबकि शिक्षा निदेशालय का आदेश था कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर 11 जुलाई से पढ़ाई शुरू कराएं। ये सभी स्कूल हिंदी माध्यम स्कूलों की जगह खोले गए हैं। पहले से कार्यरत शिक्षकों ने प्रवेश प्रक्रिया तो पूरी करा दी लेकिन विभाग इनमें एक भी शिक्षक की नियुक्ति या पदस्थापन नहीं कर पाया।

विभाग को इसके लिए कोई नई भर्ती नहीं करनी बल्कि हिंदी माध्यम के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में से ही इंटरव्यू के जरिए अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने के योग्य शिक्षकों का चयन करना है। पूर्व में खोले गए 1000 से ज्यादा महात्मा गांधी स्कूलों में भी इसी तरह शिक्षक लगाए गए थे। इसके बावजूद विभाग शिक्षक लगाना तो दूर, इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाया।

इस पर शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल का कहना है कि जल्द ही इन स्कूलों में शिक्षक लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उधर, शिक्षकों व किताबों के अभाव में हालात ये हैं कि अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश ले चुके बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं लेकिन उन्हें हिंदी के शिक्षक खाली बैठाकर घर भेज रहे हैं।

हर स्कूल में 23 का स्टाफ यानी कुल 4922 शिक्षक और स्टाफ चाहिए: प्रिंसिपल, 6 ग्रेड सैकंड टीचर, 5 लेवल-1 व 2 लेवल-2 टीचर, 1 ग्रेड सैकंड शारीरिक शिक्षक, 1 एलडीसी, 1 यूडीसी, 1 लाइब्रेरियन, 1 कंप्यूटर शिक्षक, 1 लैब असिस्टेंट, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

पुराने 221 स्कूलों में भी लेवल 1-2 के शिक्षक नहीं: पूर्व में खोले गए 221 स्कूलों में भी अब तक लेवल-1 व लेवल-2 के शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार साल 2023 तक सरकार दो हजार और स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूलों में परिवर्तित करेगी।

तीन साल पहले खोले गए स्कूलों में इस सत्र से 11वीं कक्षा शुरू, लेकिन पढ़ाने को लेक्चरर्स वहां भी नहीं: 2019 में सिर्फ जिला स्तर पर अंग्रेजी स्कूल खोले थे। वहां इस साल 11वीं कक्षा शुरू हो चुकी है। इनमें पहले से चल रहे संकाय यथावत रहेंगे लेकिन विज्ञान संकाय अनिवार्य होगा। इन स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम वाले व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं हुई है। हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे व्याख्याता ही इस साल 11वीं में आए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं।

2120 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन बढ़ाएगी गहलोत सरकार

तीन अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर यूनिट सीएम ने की अप्रूव, छबड़ा-कालीसिंध में बढ़ेगा प्रोडक्शन

हिलव्यू समाचार

जयपुर। बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान को राहत देने के लिए सरकार 3 नए थर्मल बेस पावर प्लांट लगाएगी। जिससे 2120 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बारां जिले में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नीक बेस्ड थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में 660-660 मेगावाट कैपेसिटी की दो यूनिट लगाई जाएंगी। झालावाड़ जिले के कालीसिन्ध थर्मल पावर प्लांट में भी 800 मेगावाट कैपेसिटी का एक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। प्रपोजल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अप्रूव कर दिया है। स्वीकृति मिलने के साथ ही अब इन प्रोजक्ट्स का काम शुरू हो जाएगा। अगले 4 साल में ये यूनिट्स चालू हो जाएंगी।

15660 करोड़ 64 लाख रुपए 3 यूनिट्स पर लागत आएगी: मुख्यमंत्री की स्वीकृति से छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट विस्तार कर 9606.06 करोड़ रूपए लागत की 2 अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित यूनिट लगाई जाएंगी। साथ ही कालीसिन्ध थर्मल प्रोजेक्ट के विस्तार में 6054.58 करोड़ रूपए की लागत से 1 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी। राजस्थान सरकार बिजली प्रोडक्शन में प्रदेश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती है। गहलोत ने प्रदेश को पॉवर सरप्लस बनाने के निर्देश दिए हैं। इन यूनिट्स के लगने से लोकल एरिया का डवलपमेंट होगा। साथ ही रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। गहलोत ने बजट 2022-23 में उत्पादन निगम के थर्मल पॉवर प्लांट्स में कोयले की बचत, प्रदूषण में कमी और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर महत्वपूर्ण अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की थी।

कोल बेस्ड पावर प्लांट्स कैपेसिटी 7580 मेगावाट से बढ़कर 9700 होगी

राजस्थान में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स यूनिट्स की कुल कैपेसिटी 7580 मेगावाट है। इनमें से 3240 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट कोल इंडिया की एसईसीएल और एनसीएल से कोयला सप्लाई लेते हैं जबकि 4340 मेगावाट प्लांट राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छत्तीसगढ़ में खुदकी कैप्टिव कोल माइंस से लिंक्ड हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की आगामी 5 से 7 सालों में जो एनर्जी डिमांड होगी। उसके मद्देनजर ष्टरूने यह फैसला लिया है। प्लांटों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इस पहलू को देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं कहां उपलब्ध हैं, जहां नए प्लांट कम कीमत पर लगाए जा सकते हैं। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट ज्यादा ईको फ्रेंडली हैं। पुरानी पावर यूनिट्स में कार्बन और गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है। कोल कंजम्पशन भी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट्स में कम आता है।

कांग्रेस संगठन में नई नियुक्तियां जल्द

प्रदेश में एक साथ तीनों स्तर के संगठन अध्यक्षों की नियुक्तियां, अगले महीने 29 जिलों में नए अध्यक्ष

जयपुर (कासं.)। कांग्रेस अगले माह अपने संगठन के सभी स्तर के पदाधिकारियों की घोषणा करेगी। संगठन स्तर पर राजस्थान में कांग्रेस के अभी तक 39 जिले थे, जिन्हें तीन नए निगम बनने के बाद 42 किया जा रहा है। इन सभी 42 जिलों में से 29 जिलों के अध्यक्ष सहित ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष भी अगस्त में ही घोषित कर दिए जाएंगे। मौजूदा समय में संगठन के नाम पर कांग्रेस में 13 जिलाध्यक्ष ही नियुक्त किए गए हैं। पायलट खेमे की बगावत के बाद पार्टी ने जुलाई 2020 में प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक के संगठन की इकाइयों को भंग कर दिया था। उसके बाद दिसंबर में 13 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। तब से अब तक प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान का इंतजार है।

400 ब्लॉक और 2200 मंडल में एक भी पदाधिकारी नहीं: कांग्रेस के संगठन स्तर पर प्रत्येक विधानसभा में दो ब्लॉक यानी कुल 400 ब्लॉक तथा 2200 मंडल हैं। संगठन की सभी तरह की कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद इनमें भी अभी तक नियुक्त नहीं हुई है। अध्यक्ष बनने के बाद ही उनकी कार्यकारिणी बनाई जा सकेगी। पूर्व में कांग्रेस ने मार्च तक सभी संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी, लेकिन देरी हो गई।

चुनाव प्रक्रिया लगभग पूरी, घोषित होना शेष: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इस माह में मंडल अध्यक्ष भी तय कर लिए जाएंगे। इसके बाद अगस्त में जिलाध्यक्ष से लेकर ब्लॉक व मंडल के अध्यक्ष घोषित कर दिए जाएंगे।

सदस्यता अभियान : 41 लाख सदस्य, इनमें 21 लाख डिजिटल: कांग्रेस ने मई तक चलाए सदस्यता अभियान में 21 लाख डिजिटल सदस्य बनाए। पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पर 20 लाख ऑफलाइन सदस्य बनाने का दावा किया है। दोनों मिलाकर पार्टी के अब राज्य में 41 लाख सदस्य हो गए।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद भी खाली: महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी इस समय खाली है। रेहाना रियाज चिश्ती के महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रेहाना ने इस्तीफा दे दिया था।

जयपुर-जोधपुर समेत 10 से ज्यादा शहरों में मकान महंगा होगा: हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाई ज़मीनों की कीमतें

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने राज्य में बसाई अपनी आवासीय स्कीम और खाली पड़ी जमीनों की रिजर्व प्राइज में इजाफा किया है। करीब 3 साल बाद बोर्ड ने इन जमीनों की कीमतों में 8.51 से लेकर 66 फीसदी तक का इजाफा किया है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जयपुर के मानसरोवर योजना में की है। बोर्ड के इस निर्णय से न केवल बोर्ड की योजनाओं में भविष्य में मकान खरीदना महंगा होगा, बल्कि पुराने मकानों की रजिस्ट्री करवाने में भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।

2 साल तक नहीं बढ़ाई थी कीमतें: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने आखिरी बार जमीन की रिजर्व प्राइज साल 2019 में बढ़ाई थी। साल 2020 में कोविड आने के बाद जमीनों की रिजर्व प्राइज को नहीं बढ़ाया गया था। इसके बाद साल 2021 में भी सभी आवासीय अभियंताओं से जमीन की रिजर्व प्राइज बढ़ाने के प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन उस समय भी कोविड के विषम परिस्थितियों का हवाला देते हुए बोर्ड ने कीमतें नहीं बढ़ाई थी।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में सबसे ज्यादा ने जो नई आवासीय आरक्षित दरें जारी की है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जयपुर की मानसरोवर स्कीम में की है। यहां साल 2019 तक आवासीय आरक्षित दर 15 हजार 815 रुपए प्रति वर्गमीटर थी, जिसे 66 फीसदी तक बढ़ाकर 26 हजार 180 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया। सूत्रों की माने तो आवासीय आरक्षित दर उस एरिया में किए गए डवलपमेंट पर होने वाले खर्चे पर होती है। जयपुर के मानसरोवर में वर्तमान में सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है, जो करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है।

अवैध निर्माण सील खोलने के लिए बनी पॉलिसी

जमा करवानी होगी सिक्योरिटी राशि; जेडीए कमिश्नर, डीएलबी डायरेक्टर और यूआईटी सचिव को मिली पावर

जयपुर। राजस्थान में सील हुए अवैध निर्माण को खोलने के लिए राज्य सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में सील मकान, दुकान या अन्य निर्माण को खोलने के लिए अब स्थानीय स्वायत्त शासन निदेशालय भिजवानी होगी। DLB डॉयरेक्टर के पास ही सील खोलने के अधिकार होंगे। वहीं विकास प्राधिकरण और यूआईटी एरिया में कमीश्नर और सचिव के पास सील खोलने के अधिकार होंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने आज इस नीति को जारी किया है।

सील खुलवाने से पहले देनी होगी सिक्योरिटी राशि: जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर बने विकास प्राधिकरण, यूआईटी, नगर निगम या पालिका क्षेत्र में बिना स्वीकृति निर्माण करने पर अगर सील होता है तो उसे खुलवाने के लिए आवेदक को बिल्टअप एरिया की 50 रुपए प्रतिवर्ग फीट की दर से सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी। इसके बाद 60 दिन में निर्माण का अप्रूवल लेना होगा।

इसी तरह व्यक्ति ने अगर भवन निर्माण की स्वीकृति ले रखी है और उस स्वीकृति से ज्यादा और सैटबैक में अवैध निर्माण कर लेता है, तो ऐसे प्रकरण में सील किए गए भवन को खुलवाने से पहले 300 रुपए प्रतिवर्ग फीट की दर से सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी और 60 दिन में अवैध निर्माण हटाना होगा। इसी तरह लैण्ड यूज के विपरित जाकर अगर कोई निर्माण करता है तो ऐसे मामले में सील बिल्डिंग को खुलवाने के लिए अवैध बिल्टअप क्षेत्र पर 300 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से सिक्योरिटी राशि जमा करवाकर 90 दिन के अंदर लेंड यूज चेंज कराना होगा। इसके अलावा कृषि भूमि का बिना कन्वर्जन करवाए अगर कोई निर्माण करता है तो ऐसे मामले में मौके डीएलसी रेट्स का 25 प्रतिशत की दर से सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी।

अनुमति नहीं लेने पर जब्त होगी सिक्योरिटी राशि: सील भवन को खोलने के दिन से लेकर निर्धारित दिन तक आवेदक को निर्माण स्वीकृति या भू-उपयोग परिवर्तन या अवैध निर्माण हटाना होगा। अगर कोई आवेदक निर्धारित समय सीमा में अनुमति नहीं लेता है तो उसकी जमा सिक्योरिटी राशि को प्रशासन जब्त कर लेगा। अगर आवेदक समय पर अनुमति लेता है तो 10 फीसदी राशि प्रशासनिक शुल्क के रूप में काटकर शेष 90 फीसदी राशि लौटाई जा सकेगी।

अब भवन सील करने से पहले बनाना होगा मौके का नक्शा: नई नीति के तहत अब निकाय के अधिकारी कोई भी भवन को सील करने पहुंचता है तो उसे सील किए जाने वाले भवन का मौका नक्शा बनाना होगा। इसमें ये बताना होगा कि स्वीकृत किए गए नक्शे में कहां निर्माण करना था, कितना निर्माण अवैध किया दोनों को अलग-अलग रंग में दर्शाना होगा, ताकि सील खोलने के दौरान पता रहे कि भवन मालिक ने सील भवन के दौरान कोई नया निर्माण तो नहीं कर लिया।

धार्मिक भावना भड़काने वालों पर खाचरियावास का बयान: बोले... केन्द्र सरकार सख़्त क़ानून बनाए, चुनाव लड़ने से रोके

जयपुर। देशभर में धर्म के नाम पर सोशल मीडिया पर चल रहे भड़काऊ बयान, पोस्ट को लेकर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर एक सख़्त कानून लेकर आए, ताकि ऐसा करने वालों पर सख़्त कार्यवाही हो सके। चुनाव के समय जो धर्म के नाम पर इंटरफेयर करते है भाषण देते है उसको चुनाव लड़ने से रोका जाए, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। क्योंकि उनका तो एजेंडा ही यही होता है।

दरअसल आटा, दाल, चावल पर जीएसटी लगाने के मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान सवाल पूछा गया कि अमेरिका की एक एजेंसी ने ऐसा दावा किया है कि सोशल मीडिया पर हिंदुओं पर ज्यादा टिप्पणी की जा रही है। इस पर बोलते हुए खाचरियावास ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाए और एक एक्ट पास करे। ये कानून बहुत सख़्त होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई आदमी सोशल मीडिया पर बहुत झूठ बांट रहा है।

मस्जिद को 100 करोड़ रुपए देने का फैलाया झूठ, जबकि मस्जिद वाले सरकारी पैसे लेते ही नहीं: खाचरियावास ने कहा कि मैने पिछले दिनों देखा कि ऐसा झूठ ही बोला जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने दरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए मस्जिद में दे दिए।

हिलव्यू समाचार

hillviewsamachar@gmail.com

04

जयपुर, गुरुवार, 21 जुलाई, 2022

नूपुर शर्मा से डिबेट करने वाले रहमानी का अजमेर कनेक्शनः सरवर चिश्ती बोला...

PFI-SDPI मुसलमानों की मददगार, इनका साथ दें

हिलव्यू समाचार

जयपुर। अजमेर दरगाह के अंजुमन सैय्यद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती का विवादों से पुराना नाता रहा है। वे पीएम मोदी से लेकर जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे कई संगठनों पर भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। अब उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) की वकालत करते नजर आ रहे हैं। इसमें नूपुर शर्मा के साथ विवादित डिबेट करने वाला तस्लीम रहमानी भी नजर आ रहा है।

पीएफआई पर जांच एजेंसियां हमेशा सवाल उठाती रही हैं और कई आतंकी घटनाओं को लेकर भी इससे जुड़े लोगों से पूछताछ हुई है। हाल ही में पटना में भी PFI और SDPI से जुड़े 20 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एजेंसियां PFI को आतंकी संगठन सिमी का बदला रुप मानती हैं।

मुसलमान का मददगार बताया: चिश्ती का यह वीडियो अजमेर का बताया जा रहा है, लेकिन यह कब का है इसको लेकर जानकारी नहीं है। वीडियो में चिश्ती कह रहा है- PFI को गोदी मीडिया बड़ा बदनाम कर रही है। PFI और SDPI जैसी तंजीमे मुसलमानों की आवाज उठाती है और उनकी मदद करती है। उसके साथ PFI पदाधिकारी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के नेता भी वीडियो में हैं। इसमें SDPI नेता तस्लीम रहमानी, PFI का अनीस, SDPI का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी, राजस्थान PFI अध्यक्ष आसिफ शामिल है।

PFI की पॉलिटिकल विंग है SDPI: साल 2009 में बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का ही राजनीतिक संगठन माना जाता है। हाल में बिहार के पटना में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले 11 जुलाई को आईबी के इनपुट पर बिहार पुलिस ने कार्रवाई कर आतंकियों के नेटवर्क का खुलासा किया था। इस दौरान पकड़े गए 3 आरोपियों के पास इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। इसमें दर्ज प्लान पर काम करते हुए वो अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस साजिश में शामिल जिन 26 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, वो सभी आरोपी PFI और SDPI से जुड़े हुए है। इससे पहले साल 2006 में मुंबई और 2008 में अहमदाबाद विस्फोटों में PFI का नाम आया था।

चिश्ती के पहले भी दो वीडियो आये थे सामने: 26 जून को अजमेर में सकल हिन्दू समाज ने शांति मार्च निकाला था। इसके बाद सैय्यद सरवर चिश्ती का एक वीडियो सामने आया। जिसमें वो कह रहा है कि मुस्लिम समाज ने नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जुलूस निकाला था, लेकिन इसके बाद हिन्दू समाज ने जुलूस क्यों निकाला? इससे भावनाएं आहत हुई और मुसलमान ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

प्रशासन की दी गई जुलूस निकालने की इजाजत से जले पर नमक छिड़कने का काम हुआ है। इससे हम दुखी है। वहीं एक दूसरे वीडियो में वो 15 जून को अंजुमन सैय्यद जादगान के चुनाव के बाद संबोधित करते दिखा कि ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ की दरगाह व नबी की शान में गुस्ताखी कभी कबूल नहीं करेंगे और अगर ऐसा करोगे तो पूरा हिन्दुस्तान हिल जाएगा।

बेटे का भी विवादित वीडियो: हाल ही में चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती का भी वीडियो सामने आया था, जिसमे वो नुपूर शर्मा सहित हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयानबाजी करता दिखा। इस वीडियो पर बवाल होने के बाद बुधवार रात आदिल ने फिर से एक वीडियो पोस्ट कर माफी भी मांगी।

मोदी पर दिया था विवादित बयान: 10 साल पहले कर्नाटक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मंच से सार्वजनिक तौर पर भाषण देते हुए सैयद सरवर चिश्ती ने तब नरेंद्र मोदी के PM बनने की अटकलों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सभी मुसलमान आतंकवादी बन जाएं। इसके बाद उस पर वहां मामला भी दर्ज हुआ था।

एक नज़र

तेज़ बारिश को पार करते हुए, 80 किलोमीटर से आकर किया देहदान

हिलव्यू समाचार

कोटा। नेत्रदान अंगदान और देहदान के लिए अनवरत कार्य कर रही है,संभाग की एकमात्र संस्था शाइन इंडिया फाउंडेशन द्धारा आज पुनः 80 किलोमीटर दूर कोटा से एक पुण्यात्मा का देहदान एसआरजी मेडिकल कॉलेज,झालावाड को प्राप्त हुआ है । इस तरह से 9 महीने में,झालावाड़ का यह चौथा देहदान है । इससे पूर्व भी शाइन इंडिया फाउंडेशन द्धारा 150 किलोमीटर की यात्रा करने के उपरांत बाराँ जिले समरानीया कस्बे,निवासी श्रीमति कमलाबाई जी का देहदान झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुआ था ।

संभाग में देहदान के लिए कटिबद्ध संस्था को शास्त्री नगर निवासी श्रीमान रघुनंदन सिंह पोखर जी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, परिजन चाहते थे कि,पिता जी की अंतिम इच्छा,नेत्रदान और देहदान का कार्य सम्भव हो सके । बेटे वीरेश कुमार और अनुराग सिंह ने परिवार के अन्य सदस्यों से सहमति लेने के उपरांत, शाइन इंडिया को नेत्र-देहदान कार्य सम्पन्न करवाने के संपर्क किया।

संस्था सदस्यों को सूचना मिलते ही,सर्वप्रथम रघुनंदन जी का नेत्रदान संपन्न कराया,उसके उपरांत डॉ कुलवंत गौड़ ने परिजनों से अनुरोध किया कि, झालावाड मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे,बच्चों के पास में अध्ययन करने के लिए मृतदेह नहीं है,यदि परिजन सहमति देते हैं,तो हम अपने खर्चे पर एंबुलेंस लेकर रघुनंदन जी के पार्थिव शव को मेडिकल कॉलेज झालावाड़ को दान कर सकते हैं,जिससे भावी चिकित्सकों को अध्ययन करने के लिए मृत देह प्राप्त हो सकेगी ।80 किलोमीटर दूर जाकर देहदान की बात को लेकर सबसे पहले परिजन असमंजस में पड़ गये,परंतु पुनः समझाइश करने के बाद बहु युगल सिंह,गौरी सिंह,दीक्षा चौहान व पौत्र ऐश्वर्य,बेटी रिद्धिमा सिंह ने परिवार के अन्य सदस्यों को,झालावाड़ जाकर देहदान करने के लिये राज़ी कर लिया । तेज़ बारिश में दोपहर 2 बजे,डॉ कुलवंत गौड़,पुत्र वीरेश,भुवनेश और टिंकू ओझा कोटा से रघुनंदन जी के पार्थिव शव को कोटा से एम्बुलेंस लेकर झालावाड़ को रवाना हुए ।डॉ मनोज शर्मा ने संस्था सदस्यों और शोकाकुल परिवार के सदस्यों का आभार जताया।

जयपुर में 5 पर हमला करने वाले लेपर्ड की मौतः सिर पर लगी थी चोट

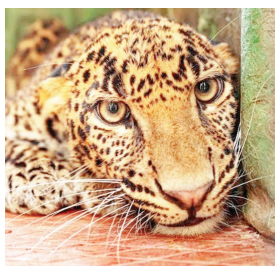

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। गत गुरुवार सुबह जिस लेपर्ड ने चंदवाजी इलाके दहशत फैला दी। शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज कर जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था। उसके सिर में चोट लगी हुई थी। मूंह से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज के बाद लेपर्ड को फिर से जंगल में छोड़ा जाएगा। इससे पहले ही पिंजरे में मौत हो गई।

लेपर्ड का इलाज कर रहे डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि तीन डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इससे मौत के कारणों का पता चलेगा। मौत के कारणों को जानने के लिए डीएफओ मनफूल विश्नोई को दोपहर साढे 12 बजे फोन किया तो उन्होने लेपर्ड की मौत होने की जानकारी से इनकार कर दिया। जब बताया कि लेपर्ड की मौत हो चुकी है तो उन्होने कहा कि वह मीटिंग में थे। उन्हे जानकारी नहीं है।

दरअसल, लेपर्ड ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 4 बजे जयपुर शहर के नजदीक चंदवाजी में लेपर्ड ने एक बच्चे सहित 5 लोगों पर हमला कर दिया। सभी घायलों को जयपुर के एसएमएस व प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची। टीम को उसे ट्रैंकुलाइज करने में 4 घंटे लग गए। यहां से रेस्क्यू कर उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था।

जानकारों की मानें तो जानवर की हत्या करने पर सात साल की सजा तक हो सकती है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। साथ ही उपचार में लापरवाही भी सामने आ सकती है। लेपर्ड का विसरा जांच के लिए आईबीआरआई बरेली में भेजा जाएगा। सवाल यह है कि मौत के कारण आने के बाद भी क्या कभी वन विभाग की ओर से कभी कोई एक्शन लिया गया है। कई बार देखने को मिला है कि उपचार में लापरवाही के कारण जानवरों की मौत हो जाती है। ऐसे में जिम्मेदारो को सोचने की जरूरत है कि एक्सपर्ट मेडिकल टीम जयपुर में काम करे जिससे उपचार की कमी से तो कोई जानवर ना मरे।

जयपुर में मिला विस्फोटक का जखीरा

82 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर बरामद

हिलव्यू समाचार

जयपुर। जयपुर के रेजिडेंशियल एरिया में अवैध विस्फोटकों का गोदाम मिला है। क्राइम ब्रांच ने 82 क्विंटल 64 किग्रा. अमोनियम नाइट्रेट, 2095 जिलेटिन की छड़ें, 3250 मीटर फ्यूज वायर और 1600 डेटोनेटर बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है।

2 सगे भाई गिरफ्तार: एडिशनल DCP (क्राइम) सुलेश चौधरी ने बताया कि अवैध धंधे में लिप्त कालू राम (56) और गोपाल लाल (48) निवासी गांव मोहनवाडी हरमाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों भाई हैं। क्राइम ब्रांच टीम को रविवार दोपहर करीब 2 बजे सूचना मिली कि हरमाड़ा के मोहनवाड़ी में एक मकान में दो भाइयों ने अवैध विस्फोटक का गोदाम बना रखा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर मकान पर दबिश दी।

30 प्रतिशत फायदे में करते धंधाः सीआई खलील अहमद के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई। खलील अहमद ने बताया- गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि वह पिछले 2 सालों से अवैध विस्फोटक की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। वह अवैध विस्फोट नीमकाथाना सीकर निवासी जगदीश सिंह से खरीदते हैं। इसकी सप्लाई पत्थर की खानों में अवैध रूप से करते हैं। इस पर 30 प्रतिशन तक का मुनाफा कमाते हैं। दोनों भाई अलग-अलग विस्फोटक का धंधा करते हैं। किसी को अवैध काम का शक नहीं हो, इसलिए रेजिडेंशियल एरिया में गोदाम बना रखा था। आरोपी खुद भी पत्थर की खानों में अवैध ब्लास्टिंग करते हैं।

ये लोग अमोनियम नाइट्रेट के 50 चत्त के कट्टे को 7300 रुपए में खरीदकर जयपुर में करीब 15 हजार रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से बेच देते थे। सरकार की ओर से प्रतिबंधित अमोनियम नाइट्रेट के 148 कट्टे घर पर बने गोदाम में मिले हैं। पूछताछ में तमाम अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है।

आरएलपी विधायक बेनीवाल की स्कॉर्पियो चोरी

हिलव्यू समाचार

जयपुर। जयपुर में MLA नारायण बेनीवाल की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो शनिवार रात घर के बाहर खड़ी की थी। रविवार सुबह स्कॉर्पियो गायब मिलने पर पुलिस कमिश्ननर को कॉल किया। विधायक की स्कॉर्पियो चोरी का पता चलने पर श्याम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर पुलिस ने शहरभर में नाकाबंदी करवाई है, लेकिन चोरी गई स्कॉर्पियो और चोरों का सुराग नहीं लगा है।

SHO श्रीमोहन मीना ने बताया कि RLP के MLA नारायण बेनीवाल की स्कोर्पियो चोरी हुई है। वह विवक विहार श्याम नगर में रहते है। शनिवार रात करीब 11 बजे उनकी स्कॉर्पियो घर के बाहर खड़ी थी। सुबह करीब 7 बजे उठकर बालकनी में आकर देखा तो स्कॉर्पियो गायब मिली। MLA बेनीवाल ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को कॉल किया। शहर में नाकाबंदी के साथ ही श्याम नगर थाना पुलिस MLA बेनीवाल के घर पहुंची। पुलिस वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल रही है। MLA बेनीवाल के ड्राइवर जगदीश ने श्याम नगर थाने में स्कॉर्पियो चोरी का मामला दर्ज कराया है।

मोबाइल लूट के तीन बदमाश चढे पुलिस के हत्थेः चोरी का मोबाइल खरीदने वाला मास्टर माइंड भी गिरफ्तार

हिलव्यू समाचार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने मोबाइल स्नैचिंग कर उसे बेचने के मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को डिटेन किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 9 मोबाइल और एक पावर बाइक भी बरामद की है। हाल ही में इन बदमाशों ने श्याम नगर निवासी ललित शर्मा के साथ मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिस के बाद पुलिस ने मौके से सीसीटीवी में इन बदमाशों को पहचान लिया।

बढ़ती वारदातों के बाद सीएसटी ने इलाके में दबिश देना शुरू किया, जिसके बाद गौरव उर्फ गोलू और सुमित को गिरफ्तार कर इन के साथ वारदातों में शामिल एक नाबालिग को निरुद्ध किया। आरोपियों ने बताया कि वह नशे के आदि हैं। मोबाइल लूटने के बाद सुशीलपुरा में रहने वाले बसंत जाटव को बेचते थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गुरुवार को बसंत जाटव को भी गिरफ्तार कर लिया। बसंत जाटव लूटे गए मोबाइल के लॉक तोड़ने में मास्टर माइंड है। वह मोबाइल को सस्ते दामों में इन बदमाशों से खरीद कर उसे आगे बेच दिया करता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी बदमाश शहर में दो दर्जन से अधिक मोबाइल लूट की वारदातें कर चुके हैं।

पहली बार पकड़े गए तीनों बदमाश: पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि इन तीनों का पहला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए इन पर किसी ने शक नहीं किया। ये बदमाश पावर बाइक लेकर वारदात को निकलने से पहले बाइक के आगे और पीछे की नम्बर प्लेट हटा दिया करते थे। जिससे किसी को इन की जानकारी नहीं मिले।

छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई अध्यक्ष अभिषेक ने सीएम गहलोत से की मुलाकात, दिया ज्ञापन

हिलव्यू समाचार

जयपुर। प्रदेश में पिछले दो साल से बंद छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग तेज होने लगी है। इसी मांग को लेकर छात्रसंगठन एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। चौधरी ने ज्ञापन में कहा कि कोविड के कारण पिछले दो साल से छात्रसंघ चुनाव नहीं हो पाए हैं, अब परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं और छात्रसंघ चुनाव को राजनीति की पहली पाठशाला माना जाता है, आपने खुद छात्रसंघ चुनाव से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने सीएम गहलोत को बताया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, के साथ विधानसभा चुनाव हुए हैं लेकिन छात्रसंघ चुनाव नहीं हो पाए। पूरे प्रदेश भर के युवाओं की मांग है कि इस सत्र में छात्रसंघ चुनाव करवाए जाएं जिससे प्रदेश की छात्र शक्ति को मजबूती मिले और छात्र छात्राओं के मुद्दों को मजबूत नेतृत्व मिल सके। गौररतलब है कि पिछले काफी समय से विवि के छात्रनेता छात्रसंघ चुनाव करवाए जाने की मांग कर चुके हैं।

छात्रनेता लोकेंद्र रायथुलिया ने इसी मांग को लेकर विवि में प्रदर्शन करने के साथ ही कई दिनों तक धरना भी दिया था, जिसे प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया था।

CRPF जवान का 4 दिन बाद अंतिम संस्कार

पत्नी को मिलेगी नौकरी, DIG भूपेंद्र समेत 9 का ट्रांसफर

हिलव्यू समाचार

जोधपुर। जोधपुर CRPF ट्रेनिंग सेंटर के जवान नरेश जाट को गुरुवार शाम अंतिम विदाई दी गई। विवाद के कारण परिवार वालों ने पोस्टमॉर्टम के बाद से शव नहीं उठाया था। पिछले 4 दिनों से परिवार वाले धरना दे रहे थे। आखिर दिल्ली से CRPF ADG रश्मि शुक्ला जोधपुर पहुंचीं। उन्होंने करीब 2 घंटे नरेश के परिवार वालों से बात की, तब जाकर सहमति बनी। जवान नरेश की पत्नी का नौकरी दी जाएगी। IG विक्रम सहगल, सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद शाम करीब 4 बजे नरेश का शव उठाया गया। 11 जुलाई को नरेश ने सरकारी क्वार्टर में खुद को गोली मार ली थी।

9 लोगों पर लगाए टॉर्चर के आरोप: परिवार वालों ने CRPF DIG भूपेंद्र सिंह सहित जिन 9 लोगों पर नरेश को टॉर्चर के आरोप लगाए थे। उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं, 7 महीने पहले सब इंस्पेक्टर विकास कुमार सुसाइड केस को भी नए सिरे से दर्ज किया जाएगा।

नरेश जाट मामले में मांगों पर सहमति बनने के बाद शव को शाम 4.15 बजे CRPF ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जवान के पिता लिखमा राम रो पड़े। उन्हें सांसद बेनीवाल ने संभाला। उन्होंने पगड़ी उतार कर बेटे को अंतिम विदाई दी। CRPF एडीजी रश्मि शुक्ला ने जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। आईजी विक्रम सहगल, कमिश्नर रवि गौड़, डीसीपी अमृता दुहन, सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी श्रद्धांजलि दी।

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी

'नरेश जाट अमर रहें' के नारे लगते रहे। शाम 4.30 बजे जवान का तिरंगे में लिपटा शव पैतृक गांव पाली के राजोला रवाना किया गया। वहां सैन्य सम्मान के साथ शाम 6 बजे अंतिम संस्कार किया गया। ADG रश्मि शुक्ला ने कहा- मामले की गंभीरता देखते हुए गृह मंत्रालय ने ऐसे मामले रोकने के लिए कमेटी बनाई है। जोधपुर प्रशिक्षण केंद्र से डीआईजी भूपेंद्र सिंह सहित नौ लोगों का तबादला किया गया है। कुछ कर्मचारी सूरतगढ़ से भी हटाए गए हैं। उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी। 7 महीने पहले CRPF के सब इंस्पेक्टर विकास कुमार ने भी आत्महत्या की थी। उस मामले को भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में लिया गया है।

इन बातों पर बनी सहमति

जवान नरेश जाट व विकास कुमार के सुसाइड मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश जारी हुए हैं। इसकी रिपोर्ट 15 दिन में आईजी विवेक

वैद्य देंगे। मृतक के परिवार को सीआरपीएफ के नियमानुसार 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मृतक की पत्नी को नौकरी मिलेगी। मृतक की बेटी की 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च सीआरपीएफ उठाएगी। नरेश की पत्नी को पुनर्विवाह करने तक पेंशन मिलेगी। जवान विकास कुमार की आत्महत्या मामले में केस दर्ज होगा। इन मांगों को लेकर परिवार वालों के साथ RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने 3 दिन तक मॉर्च्यूरी के बाहर धरना दिया था।

एक नज़र

विप्र पुजारियों को आर्थिक संबल देने की तैयारी

जिन मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी, उन्हें ही मिलेगा अनुदान

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की वेबसाइट अपलोड होने के बाद ही मंदिरों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके लिए बोर्ड वेबसाइट बनवा रहा है। इस वेबसाइट पर उन्हीं मंदिरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनके पुजारी ब्राह्मण हैं। बोर्ड इन मंदिरों के विप्र पुजारियों को आर्थिक संबल देने के लिए अनुदान भी देगा। बोर्ड सरकार से 4000-5000 रुपए तक का अनुदान देने की सिफारिश कर सकता है। उधर बोर्ड ने देवस्थान विभाग से राज्य के लगभग 40 हजार मंदिरों की सूची ली है।

विप्र कल्याण बोर्ड की वेबसाइट अपलोड होने के बाद ही हो सकेगा मंदिरों का रजिस्ट्रेशन: विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य विप्र समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं की पहचान व सर्वेक्षण करना और उनके समग्र विकास के लिए कार्य करना है। इसी उद्देश्य के तहत मंदिरों के ब्राह्मण पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकारी अनुदान दिया जाएगा। देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड मंदिरों के अलावा उन मंदिरों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिनका अब तक कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन व अनुदान में सिर्फ विप्र पुजारियों को ही शामिल किया जाएगा।

विप्र समाज हित में बोर्ड के कार्य

- मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं व ट्रस्ट में सेवा, पूजा करने वाले बतौर कार्मिक कार्य करने वाले पुजारियों, सेवकों तथा कर्मचारियों को रोजगार के बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अध्ययन कर राज्य सरकार को सुझाव देना।
- इन वर्गों के लोगों की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए विप्र समाज के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उपाय बताना।
- इन वर्गों के विकास से संबंधित योजनाओं का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को अपनी अभिशंषा के साथ भेजना।
- ब्राह्मण समाज की सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने के लिए राज्य सरकार को अभिशंषा के साथ सुझाव देना।
- विप्र समाज के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव देना।

दशहरा महोत्सव के लिए ब्रोशर का विमोचन

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। विद्याधर नगर स्टेडियम विकास समिति की ओर से प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी स्टेडियम में आयोजित होने वाले दशहरा महोत्सव के लिए ब्रोशर विमोचन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ (आरटीडीसी चेयरमैन) पवन गोदरा राज्यमंत्री द्वारा किया गया। समिति के सचिव अनिल सन्त ने बताया कि दशहरा महोत्सव का आयोजन 25 सितम्बर से किया जाएगा। इस अवसर पर विद्याधर नगर स्टेडियम विकास समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र कविया, सचिव अनिल संत, डॉ सुनील शर्मा, पंकज पचलंगिया, राजेन्द्र राठौड, टिंकू राठौड़, आदि ने विघ्नविनाशक को निमंत्रण देकर कार्यक्रम को निर्विघ्न सफल बनाने की प्रार्थना की। अनिल सन्त ने बताया कि दशहरा महोत्सव में हर वर्ष की भाँति इस वर्ष अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देशभर से नामी-गिरामी हस्तियाँ भाग लेंगी।

कावड़ियों का होगा गलता में रजिस्ट्रेशन: सम्बंधित थाने में दी जाएगी कावड़ियों की जानकारी, जयपुर में एक हजार शिवालय

हिलव्यू समाचार

जयपुर। हिंदू धर्म का पवित्र सावन पर्व गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। देश में फैले सांप्रदायिक तनाव के बीच इस बार सावन के महीने में होने वाले तमाम आयोजनों को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए है। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि जयपुर में करीब एक हजार शिवालय है , जहां सावन के महीने में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अकेले नार्थ जिले में करीब 400 शिवालय हैं। जहां भक्तों का तांता लगा रहता है ।

ऐसे में इन शिवालयों की सुरक्षा के साथ ही शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि सावन के महीने में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर धर्म गुरूओं के साथ ही शांति समिति और सीएलजी सदस्यों बैठक की गई है। अब पहली बार जयपुर में कांवड़ यात्रा में जाने वाले हर शिवभक्त का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

गलता से कांवड़ यात्रा के लिए जल लाने के दौरान ही पुलिसकर्मी रजिस्ट्रेशन कर रूट के संबंध में संबंधित पुलिस थाने पर सूचना देगा। साथ ही रूट के दौरान पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे जो कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इस दौरान ड्रोन कैमरों से भी निगरानरी रखी जाएगी।

वहीं, जयपुर शहर में डीजे पर पाबंदी के आदशों की पालना पुलिस सख्ती से कराएगी। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि गलता पर ही पुलिकर्मी कावड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर भेजेंगे साथ ही सम्बंधित थाना पुलिस को भी जानकारी दी जाएगी की कावडिये कावड़ लेकर रवाना हो गए हैं। जिस पर पुलिस टीमें सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगी।

चुनाव से पहले कृषि कनेक्शन देकर वोट बैंक साधने की मुहिम

4 लाख 88 हजार किसानों को बिजली देगी गहलोत सरकार

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार 4.88 लाख पेंडिंग और नए कृषि बिजली कनेक्शन जारी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली कम्पनियों को युद्ध स्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने को कहा है। किसानों को साधने के लिए बिजली से जुड़े सभी पेंडिंग काम टाइम टेबल बनाकर निपटाने को भी कहा गया है। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में गहलोत ने कहा सरकार प्रदेश में बिना रुकावट बिजली की सप्लाई के साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए डेडिकेटेड है। अगले दो साल में कुल 4 लाख 88 हजार 625 नए और पेंडिंग कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू की है,जिसका मेन मकसद किसानों को आर्थिक तौर पर सहायता देना है।

पहले फेज में 2.31 लाख कृषि कनेक्शन का टारगेट: गहलोत ने बिजली विभाग और बिजली कम्पनियों के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कृषि

कनेक्शन जारी करने के साथ बिजली और उपकरणों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करने को कहा है। साथ ही लेबर रेट कॉन्ट्रेक्ट (ष्टरुक्रष्ट) के ठेकेदारों को जरूरी सामान मुहैया कराने में आ रही कठिनाइयों के जल्द निपटारा के भी निर्देश दिए। पहले फेज में 2022-23 के लिए 2 लाख 31 हजार 344 कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। दूसरे फेज में 2023-24 में 2 लाख 58 हजार 625 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का टारगेट रखा गया है।

जयपुर,जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को यह टारगेट दिया: पहले फेज में जयपुर डिस्कॉम को 71207, जोधपुर डिस्कॉम को 90137 और अजमेर डिस्कॉम को 70 हजार कनेक्शन जारी करने का टारगेट दिया गया है। लगभग 50 प्रतिशत कनेक्शन के काम टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर और बाकी 50 फीसदी लेबर लेट कॉन्ट्रैक्ट(सीएलआरसी) के माध्यम से करवाए जाएंगे। टर्नकी में कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक कंपनी सभी फैसिलिटी, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इस्टेब्लिशमेंट, आफ्टर मार्केट सपोर्ट, टेक्नीकल सर्विस और डवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाती है। सभी इक्विपमेंट खरीदार फर्म को उपलब्ध करवाती हैं। जिम्मेदार कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में सहमति के अनुसार काम करती हैं।

कांग्रेस के ख़िलाफ़ गुजरात में प्रचार करेंगे राजस्थान के बेरोजगार

उपेन बोले... राजस्थान सरकार की वादा ख़िलाफ़ी का देंगे करारा जवाब

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान की बेरोजगार गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। मंगलवार को प्रदेश के बेरोजगारों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के साथ वादा ख़िलाफ़ी की है। ऐसे में अब हम कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी के अंतर को गुजरात की जनता को बताएंगे। ताकि आम जनता कांग्रेस की असलियत पता चल सके।

उपेन यादव ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेसी नेताओं ने बेरोजगारों से कई वादे किए थे। लेकिन आज तक वह वादे अधूरे हैं। इसके साथ ही राजस्थान और लखनऊ के समझौते को भी अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए मजबूरन राजस्थान के बेरोजगार गुजरात में जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। ताकि कांग्रेस के आला नेताओं को भी राजस्थान की हकीकत का पता चल सके।

दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही राजस्थान के 2 दर्जन से अधिक मंत्री और विधायक गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। प्रदेश के आला नेताओं ने गुजरात पहुंचना शुरू भी कर दिया है। वहीं नेताओं के बाद अब प्रदेश के बेरोजगार भी कांग्रेसी के खिलाफ प्रचार करने के लिए गुजरात जाएंगे। ऐसे में देखना होगा गुजरात चुनाव में जनता राजस्थान के बेरोजगारों की बात सुनती है, या फिर नेताओं की।

500 ऑक्सीजन प्लांट अप्रशिक्षित स्टाफ के भरोसे: पीएसए प्रशिक्षण के बाद ऑल इंडिया एग्जाम पास कर चुके 266 नर्सिंग कर्मी कर रहे नौकरी का इंतज़ार

हिलव्यू समाचार

जयपुर। कोरोना के दौरान सरकार ने ऑक्सीजन प्लांटों पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। न केवल मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों बल्कि जिला, उपजिला, सैटेलाइट और सीएचसी पर भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए गए, लेकिन अब इन उपकरणों के संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अप्रशिक्षित स्टाफ के हाथों में है। चौंकाने वाली जानकारी यह है कि बड़े-बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांटों की कमान नर्सिंग और वार्ड बॉय के हाथों में है। प्रदेशभर में करीब 500 ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं। इनमें पीएम केयर्स की ओर से संचालित प्लांट भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएसए प्रशिक्षण ले चुका योग्य स्टाफ नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। केन्द्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के 400 आईटीआई प्रशिक्षितों ने पहले तो 180 घंटे का पीएसए यानि हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्रशिक्षण लिया। फिर ऑल इंडिया स्तर पर 266 नर्सिंग कर्मी ने ऑनलाइन भी परीक्षा पास की, लेकिन अब नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।

कांवटिया का ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है।

- **आईटीआई के साथ प्रशिक्षण जरूरी :** ऑक्सीजन प्लांट संभालने के लिए ऑपरेटर का आईटीआई होल्डर होना जरूरी है। प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
- **जयपुर में 20 प्लांट :** राजधानी में 20 ऑक्सीजन प्लांट हैं। एसएमएस अस्पताल में 10 हैं।

> प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांटों के लिए ऑपरेटर के 401 पदों पर संविदा परएनएचएम की पीआईपी में अनुमति मिल चुकी है। जल्द ऑक्सीजन प्लांटों पर प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति होगी।
>
> -वैभव गालरिया
> प्रमुख सचिव
> (मेडिकल शिक्षा)

- मेडिकल कॉलेज व अन्य सरकारी अस्पतालों के ऑक्सीजन प्लांट में 50 बायोमेडिकल इंजीनियर और 400 से ज्यादा ऑपरेटर चाहिए।
- अप्रशिक्षित के होने से अस्पतालों के वार्डों में आईसीयू और ऑपरेशन के दौरान मरीजों की जान को खतरा रहता है। पीएम केयर्स की ओर से संचालित कुछ ऑक्सीजन प्लांट स्टाफ की कमी, हैड एंड टेकन ओवर और मशीनों के खराब होने से बंद पड़े हैं।
- पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से हर मिनट एक हजार लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्लांट से एक समय पर 190 मरीजों को पांच लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। वहीं 195 ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल किया जा सकता है।

मानव मल प्रबंधन के लिये आवासन मण्डल 5 शहरों में शुरू करेगा पायलट प्रोजेक्ट

वैज्ञानिक रीति से हो फिकल स्लज मैनेजमेंट: अरोड़ा

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में जैविक एवं वैज्ञानिक माध्यम से मानव मल प्रबंधन (फिकल स्लज मैनेजमेंट) पर जोर देगा। मण्डल मल के समुचित निस्तारण की योजना पर काम करने जा रहा है। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोडा ने स्वच्छ भारत अभियान- 2.0 को गति देने के उद्देश्य से दौराई, नायला, हनुमानगढ, कोटपूतली एवं बडी सादडी की योजनाओं में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिये हैं।

मण्डल के बोर्ड कक्ष में सोमवार को इस संबध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि शौचालयों से निस्तारित अपशिष्ट मल लिक्विड एवं सॉलिड रूप में सेप्टिक टैंक में पहुंचता है। समुचित प्रबंधन के अभाव में मल समय के साथ ठोस रूप लेकर जलीय एवं भू-प्रदूषण का कारण बनता है। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि बैक्टीरिया के उपयोग से मानव मल का जैविक प्रक्रिया से निस्तारण संभव है। बैक्टीरिया के सहयोग से सेप्टिक टैंक में जमा सॉलिड फिकल स्लज को लिक्विड रूप में परिवर्तित किया जाना संभव है। इससे सेप्टिक टैंकों के आउटलेट से निकलने वाले प्रदूषण स्तर को 60 से 30 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। आवासन आयुक्त ने स्वच्छ भारत अभियान की मंशा के अनुरूप मल के समुचित प्रबंधन एवं निस्तारण के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना शुरू करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य अभियन्ता के.सी. मीणा, जी.एस. बाघेला, मनोज गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नत्थूराम, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

4 अस्पताल के लिए जेडीए ने ज़मीन दी

5 अप्रैल को आईपीडी टावर के शिलान्यास पर सीएम ने सेटेलाइट अस्पताल की घोषणा की थी, चिकित्सा विभाग ने प्रोजेक्ट पेंडिंग में डाला

हिलव्यू समाचार

जयपुर। दिल्ली रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और अजमेर रोड पर चार सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाने के लिए जेडीए ने जमीन चिन्हित कर चिकित्सा विभाग को सूची भेज दी लेकिन अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को ही 'पेंडिंग' में डाल दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 अप्रैल को आईपीडी टावर के शिलान्यास पर शहर के चारों एंट्री पाइंट पर सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। जेडीए 2 महीने पहले एसएमएस से 30 किमी दूर चार जगह पर 9 से 31 हजार वर्ग मीटर तक जमीन चिन्हित कर चुका है।

जितनी जल्दी चारों सेटेलाइट अस्पताल बनेंगे, उतनी ही जल्दी एसएमएस का भार कम होगा

- दिल्ली रोड पर अचरोल स्थित साइंस टेक सिटी में 100 फीट रोड पर 10 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की गई है।
- टोंक रोड पर शिवदासपुरा में रिंग रोड प्रोजेक्ट में सेटेलाइट हॉस्पिटल के लिए 31795.66 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई है।
- आगरा रोड पर कानोता-बस्सी के बीच में खसरा नंबर 177 में हॉस्पिटल के लिए 19157.63 वर्ग मीटर जमीन चिह्नित की गई है।
- अजमेर रोड पर बालमुकुंदपुरा में अजमेर रोड से 200 मीटर अंदर 100 फीट रोड पर 9 हजार वर्गमीटर जमीन ली जाएगी।

LIFESTYLE

बनाई जाए सामाजिक और साझी व्यवस्था

समय की मांग है वानप्रस्थ संकुल

वानप्रस्थ की परिकल्पना जीवन के उस कालखंड के लिए है जब व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन के सामान्य उत्तरदायित्व पूर्ण कर लेता है और भौतिक जीवन का नेतृत्व नयी पीढ़ी को सौंप, वृहद समाज के कल्याण और अपनी अध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है. ये समय आयु के वर्षों में नहीं, वरन व्यक्ति के अपने चिंतन के आधार पर तय होता है. वानप्रस्थ आश्रम की परिकल्पना समाज में पीढ़ियों के संघर्ष को रोकने में भी सहायक हो सकती है. जीवन की गुणवत्ता और चिकित्सीय विधानों में उन्नति के कारण जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, आने वाले समय में समाज में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही उनसे सम्बंधित समस्याएं भीं. ऐसे में "वानप्रस्थ संकुल" की रचना समय की मांग है. ये आपके अभी तक देखे या कल्पना किए हुए वृद्धाश्रम नहीं होंगे जहां केवल निरीह और परिवार से परित्यक्त बुजुर्ग मृत्यु की प्रतीक्षा में समय काट रहे हों, ये सामाजिक उत्तरदायित्व और आध्यात्मिक चेतना के जागृत शक्ति केंद्र होंगे. इनकी प्रेरणा हमारी आश्रम व्यवस्था के वानप्रस्थ आश्रम से ली जा सकती है और इनकी संरचना हमारी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है.

समान आयु वर्ग के साथियों की ज़रूरत

बुजुर्ग हमें अपने आस-पास न जाने कितने परिवारों में मिल जाएंगे. वो शारीरिक रूप से किसी पर आश्रित नहीं हैं, अपना काम करने में समर्थ हैं. उनकी भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं. उनको आवश्यकता है तो समय बिताने और बात करने के लिए समान आयु वर्ग के साथियों की. बड़े नगरों के उच्चवर्गीय और विकसित क्षेत्रों के बड़े-बड़े घरों में बुजुर्ग दम्पति या दोनों में से शेष रहा कोई एक, अकेले रह रहा है. बच्चे शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी जैसे कारणों से दूसरे नगरों या देशों में रह रहे हैं. इनका जीवन अलग प्रकार के भय से ग्रस्त है. कई परिवारों में आर्थिक कारणों से, नई पीढ़ी के पास समय के आभाव से, पीढ़ियों में सामंजस्य के अंतर के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि बुजुर्गों का अपने पुत्र या पुत्री के परिवार के साथ रहना कठिन हो जाता है. 2 पीढ़ियां एक दूसरे से जूझते हुए जबरन साथ रहती हैं. दोनों ही मानसिक अवसाद से ग्रस्त.

बदली हुई सामाजिक परिस्थितियां

■ बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में ज्यादातर एक या दो संतान वाले परिवार हैं. ऐसे में यदि बच्चे किसी भी कारण से बाहर जाते हैं तो स्वाभाविक है परिवार के बुजुर्गों को अकेले ही रहना होगा. न तो सारे बुजुर्ग बच्चों के साथ बाहर जाने को तैयार होंगे और न ही सारे बच्चे ऐसी स्थिति में होंगे कि उन्हें साथ ले जा सकें. इस प्रकार प्रत्येक नगर में कार्यरत कुछ परिवारों के बुजुर्ग दूसरे नगरों में अकेले ही रह रहे होंगे.

■ क्या इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक सामाजिक और साझी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? प्रतिदिन समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में बुजुर्गों से सम्बंधित व्यथित करने वाले समाचार आते हैं. केंद्र की राजनीति में रहे प्रमुख राजपरिवार की एक महिला और एक बड़े उद्यमी को अपने आर्थिक अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है.

■ जिन परिवारों के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, उनको अत्यंत हेय दृष्टि से देखा जाता है. इसलिए कई बार केवल उस सामाजिक भर्त्सना से बचने के लिए लोग बुजुर्गों को मजबूरी मान, घर में रख लेते हैं और हर समय कोसते रहते हैं. यहां तक की पूरी बात बुजुर्गों के पक्ष की है.

■ किन्तु ये समस्या इतनी सरल भी नहीं. पूरा दोष नई पीढ़ी पर नहीं डाला जा सकता. कई बार बुजुर्गों का आवश्यकता से अधिक मोह, नई पीढ़ी के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप और हठधर्मिता भी परिवार में उनकी उपेक्षा का कारण बनती है.

इतिहास में हैं कई उदाहरण

भक्त प्रहलाद पुत्र का विवाह और माता का देहावसान होने पर पुत्र का राज्याभिषेक कर वानप्रस्थी हो गए थे. धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती महाभारत युद्ध के पश्चात वानप्रस्थी हुए. दिग्विजयी चन्द्रगुप्त मौर्य ने मात्र 52 वर्ष की आयु में वानप्रस्थी होने का निर्णय ले लिया था. आश्रम व्यवस्था से प्रेरित इन वानप्रस्थ संकुलों में आने का निर्णय लेने वाले बुजुर्ग, यहां आकर अपनी रुचि के अनुसार उत्पादक और समाजसेवा के कार्य कर सकेंगे, अपनी उन अभिरुचियों पर काम कर सकेंगे जो जीवन की आपाधापी में नैपथ्य में पड़ी रह गईं, इसके साथ ही यहां आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला मार्गदर्शन भी उपलब्ध होगा. ये समाज से कटा निराश्रित समूह नहीं, वरन समाज को समर्पित सशक्त साधना केंद्र होगा. यहां आकर रहना लज्जा का नहीं, सम्मान का द्योतक होगा. वानप्रस्थ संकुलों के निर्माण से आने वाले समय में बढ़ने वाली बुजुर्ग जनसंख्या के नियोजन की एक पूर्व व्यवस्था हो सकेगी. कुछ धार्मिक संस्थाओं और केन्द्रों ने ऐसे प्रयास किए हैं किन्तु वे उन संस्थाओं से जुड़े लोगों तक ही सीमित हैं. ऋषिकेश, वृन्दावन जैसे स्थानों पर भी ऐसे कुछ केंद्र हैं किन्तु उन तक अत्यंत सीमित जनसंख्या की ही पंहुच है. समय की मांग है कि हम वृद्धाश्रम की नकारात्मकता से बाहर आएं, वानप्रस्थ संकुल की संकल्पना करके उसे क्रियान्वित करें.

शो 'द कपिल शर्मा शो' में बॉलीवुड के मेगास्टार्स एक्टर धर्मेंद्र पहुंचे. शो में लीजेंडरी अभिनेता ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों के कुछ मजेदार और दिलचस्प किस्से सुनाए. एक पिक्चर सेगमेंट के दौरान कपिल ने धर्मेंद्र के पुराने दिनों की कुछ तस्वीरें दिखाईं, जिसमें उनका तगड़ा शरीर और सधी हुई कद-काठी साफ नजर आ रही थी. इसे देखते हुए अर्चना पूरन सिंह ने धर्मेंद्र से पूछा कि आज के एक्टर्स के पास तो खास तरह का शरीर और वेस्टलाइन बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन उनके इस शानदार शरीर का क्या राज था?

सीनियर STAR

लीजेंडरी एक्टर ने बताया अपनी फिटनेस का राज़

हर दिन 25 किलोमीटर साइकिल चलाते थे धर्मेंद्र

इस पर धर्मेंद्र ने कहा, 'जब मैं छोटा था, तो हमारे यहां हैंडपंप नहीं होते थे, इसलिए हम कुएं से पानी खींचते थे और वक्त के साथ मैं बहुत सारी बाल्टियां उठाने का आदी हो गया. मैंने बहुत कबड्डी भी खेली. मेरी जांघें वाकई बहुत दमदार हैं क्योंकि मैं हर दिन 25 किलोमीटर पैडल मारता था, जिससे मुझे फिल्म धरमवीर में मदद मिली.' धरम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ऐसी जिंदगी मिली, क्योंकि इसने कई लोगों को अनमोल सीख दी.

उन्होंने कहा, 'मैंने जिस तरह से बचपन में अपनी जिंदगी जी, एक छोटे से शहर के मध्यमवर्गीय परिवार से इस पेशे में आया और फिर कई फिल्म प्रोड्यूसर्स द्वारा रिजेक्ट किया गया. वो ऐसे दिन थे, जब मैं अपने इरादों और अपनी काबिलियत में पक्का था और इसका नतीजा यह हुआ कि मैं आज आप लोगों के सामने हूं.' धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में खुले बदन के शॉर्ट्स की परंपरा की शुरुआत की थी.

विपरीत परिस्थितियों में दिखाएं बुद्धिमानी

बोधकथा

एक आश्रम में गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देते थे. एक दिन एक शिष्य ने गुरु से कहा, 'मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, जिससे मुझे जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके. ऐसा उपाय, जिसकी मदद से हर समस्या हल हो सके.' गुरु बहुत विद्वान थे. उन्होंने कहा, 'मैं एक तरीका बता दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं. लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो.' गुरु ने अपनी बकरी की रस्सी शिष्य के हाथ में पकड़ा दी. बकरी किसी से भी आसानी से काबू में नहीं आती थी. शिष्य जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल-कूद करने लगी. बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी. शिष्य ने कुछ देर सोचा कि इसे कैसे काबू किया जाए. सोचने के बाद उसने बकरी को पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए. इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया. गुरु ये सब देख रहे थे. शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए. गुरु ने शिष्य से कहा, 'ठीक इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी से बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से हल हो सकती है. यही सफलता का मूल मंत्र है.'

सीख - विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बुद्धिमानी से ही काम करना चाहिए. धैर्य बनाए रखें और सोच-समझकर आगे बढ़ें. सबसे पहले समस्या की जड़ को समझें और फिर उसे हल करने की योजना बनाएं, तभी सफलता मिल सकती है.

ज्ञानकथा

क्षमा

देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को लगता था कि वह जो भी करेगा, सब सही है. रामायण में वनवास के समय श्रीराम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में रह रहे थे. एक दिन श्रीराम और सीता बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे. उस समय जयंत ने कौए का वेश बनाया और सोचा कि मैं परीक्षा लेता हूं कि राम कितने बलशाली हैं? ऐसा सोचकर कौए ने सीता के पैरों में चोंच मार दी. सीता को दर्द हुआ तो श्रीराम ने छोटे से तिनके का बाण बनाया और अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया. ब्रम्हास्त्र की तरह तिनके का बाण जयंत के पीछे चलने लगा तो वह डरकर भागने लगा. सबसे पहले वह अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा. इंद्र ने उससे कहा, 'तूने श्रीराम का अपराध किया है तो मैं तुझे नहीं रख सकता.' जयंत कई जगह भागा, कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसे कहीं भी मदद नहीं मिली. रास्ते में उसे नारद मिल गए. नारद ने जयंत से पूरी घटना पूछी. नारद की वजह से वह तीर थोड़ी देर वहीं रुक गया, क्योंकि वे देवर्षि थे. पूरी बात समझने के बाद नारद ने कहा, 'जयंत, तुम भूल कर रहे हो. गलती तुमने सीता और राम के प्रति की है और चाहते हो कि तुम्हें कोई दूसरा बचाए? ऐसा नहीं हो पाएगा. जाओ श्रीराम से क्षमा मांगो. वह तुम्हें क्षमा करेंगे, उसके बाद ही तुम बच पाओगे.' जयंत ने ऐसा ही किया. श्रीराम ने जयंत से कहा, 'तुम्हें दंड तो मिलेगा, लेकिन मृत्युदंड नहीं.' ऐसा कहकर श्रीराम ने उसकी एक आंख में तीर मारा और उसे जीवित छोड़ दिया.

सीख - जिस व्यक्ति के प्रति हमसे कोई अपराध हुआ है, सबसे पहले उसी व्यक्ति से हमें क्षमा मांगनी चाहिए. कुछ लोग अपराध करते हैं और कुछ पुण्य करके सोचते हैं कि पाप कट जाएंगे. यह सही नहीं है. हमें गलत काम करना ही नहीं चाहिए और अगर कुछ गलत काम हो गया है तो उसके लिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए.

निजी अस्पतालों के भरोसे बुजुर्ग

एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि ढलती उम्र में आधे से भी अधिक बुजुर्गों को अपनी सेहत की देखभाल के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है. बुजुर्गों की रुग्णता से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के लिए उनकी बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को शामिल किया गया है. स्वास्थ्य की देखभाल में होने वाले खर्च संबंधी आंकड़ों में अस्पताल में भर्ती होने, निदान, डॉक्टरों की फीस, दवाइयों, बेड चार्ज और परिवहन समेत अन्य गैर-मेडिकल खर्चों को भी शामिल किया गया है. सर्वेक्षण में शामिल 27,245 बुजुर्गों में 50.3 प्रतिशत पुरुष और 49.7 प्रतिशत महिलाएं थीं. वहीं, 9.2 प्रतिशत ग्रामीण और 8.4 प्रतिशत शहरी बुजुर्गों की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और 57.4 प्रतिशत बुजुर्ग निरक्षर थे. अध्ययन के दौरान पाया गया कि 30 प्रतिशत से अधिक बुजुर्ग गत 15 दिनों से किसी बीमारी से पीड़ित थे, जबकि बीते एक साल के दौरान अस्पताल में भर्ती होने वाले बुजुर्गों की संख्या 8 प्रतिशत थी. 80 साल की उम्र के बुजुर्गों के बीमार होने का अनुपात भी कम उम्र के लोगों की अपेक्षा अधिक पाया गया है.

निम्न आय वर्ग ज्यादा परेशान

सर्वेक्षण से एक बात यह भी उभरकर आई है कि गरीबों की अपेक्षा संपन्न लोग बीमारियों का अधिक शिकार बनते हैं और अस्पतालों में भर्ती होने के मामले भी उनमें अधिक देखे गए हैं. गरीब बुजुर्गों की अपेक्षा संपन्न वर्ग के बुजुर्ग अस्पताल में इलाज कराने के लिए 3 गुना से अधिक खर्च करते हैं. शहरी क्षेत्रों के संपन्न बुजुर्गों के मामले में यह आंकड़ा 6.6 गुना और ग्रामीण बुजुर्गों के मामले में 1.9 गुना अधिक है. इससे स्पष्ट है कि निम्न आय वर्ग के बुजुर्गों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि बीमारियां तो बढ़ रही हैं, पर उसके अनुपात में बजटीय आवंटन नहीं बढ़ रहा है. निकट भविष्य में बुजुर्गों की पुरानी बीमारियों के मामले में स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी रणनीतियों को विशिष्ट रूप से उपचार पर केंद्रित करने की जरूरत है. इसके साथ ही बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना भी जरूरी है.

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 64 प्रतिशत मामलों में बुजुर्ग निजी अस्पतालों और 35.9 प्रतिशत मामलों में सार्वजनिक अस्पतालों का उपयोग करते हैं. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को आधार माना जाए तो वहां भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है. ग्रामीण इलाकों में 61 प्रतिशत मामलों में निजी अस्पतालों और 38.6 प्रतिशत मामलों में सार्वजनिक अस्पतालों का उपयोग होता है. इसी तरह शहरों में भी 68.6 प्रतिशत मामलों में निजी अस्पतालों और 31.4 प्रतिशत मामलों में सार्वजनिक अस्पतालों का उपयोग होता है. अध्ययनकर्ताओं का कहना यह भी है कि पुरुष एवं महिलाओं में बीमारियों से ग्रसित होने और अस्पतालों में इलाज कराने के मामले समान रूप से दर्ज किए गए हैं. हालांकि, विभिन्न वर्गों के बुजुर्गों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर अस्पताल में इलाज का खर्च कम होता है. अध्ययनकर्ताओं के अनुसार बुजुर्गों की सेहत और उनकी बेहतर जिंदगी से जुड़ी किसी भी रणनीति में विभिन्न वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में असमानता को दूर करने के प्रयासों को शामिल करना जरूरी है. बीमारियों से ग्रस्त होने और उससे जुड़े खर्च की सही समझ हो तो उम्रदराज लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत करने में मदद मिल सकती है. यह अध्ययन इस दिशा में कारगर हो सकता है.

माता-पिता की ज़िंदगी को बनाएं आसान

रवि के बुजुर्ग माता-पिता अकेले रहते हैं. वह माता-पिता की आर्थिक रूप से मदद तो करते हैं, लेकिन मौजूदा स्थितियों में उनकी देखभाल की भी चिंता रहती है. उन्हें खासतौर से चोरी का डर बहुत सताता है. माता-पिता दलील देते हैं कि किसी अनहोनी के लिए घर में पर्याप्त पैसा होना जरूरी है. इससे बैंक के भी ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं. लेकिन, रवि इन बातों से संतुष्ट नहीं हैं. वह इसका समाधान खोजना चाहते हैं. वह ऐसे किसी विकल्प की तलाश में हैं, जिससे माता-पिता के पास जरूरत के समय पर्याप्त पैसा भी रहे. लेकिन, इस पैसे को उन्हें घर पर न रखना पड़े. वह अपने माता-पिता की जिंदगी को आसान और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं? उम्र के इस पड़ाव में रवि के माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता मेडिकल इमर्जेंसी होगी. मौजूदा संकट में यह वाकई चिंताजनक है. रवि को अपने माता-पिता को कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में एनरोल कराने के बारे में सोचना चाहिए. यह इमर्जेंसी और नॉन-इमर्जेंसी मेडिकल खर्चों को कवर करेगा. अगर अलग इंश्योरेंस पॉलिसी मिलनी मुश्किल है तो रवि उन्हें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जोड़ सकते हैं. उन्हें पॉलिसी के तहत सुविधाओं को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताना चाहिए ताकि माता-पिता भरोसे के साथ जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सकें. ऐसी स्थिति में उन्हें अपने साथ बहुत कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ई-वॉलेट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड

ई-वॉलेट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक और विकल्प है जो नियमित खर्चों के लिए कैश की जरूरत को कम करते हैं. मेडिकल से लेकर ग्रॉसरी आउटलेट तक ज्यादातर दुकानों में कार्ड को स्वीकार किया जाता है. रवि को एक ऐसा कार्ड चुनना चाहिए जिसकी स्वीकार्यता काफी ज्यादा हो. उन्हें मासिक कार्ड के बिलों का ऑनलाइन सेटलमेंट करने का भी इंतजाम करना चाहिए. वह अपने बैंक से माता-पिता को ऐड-ऑन कार्ड जारी करने के लिए कह सकते हैं. वजह यह कि बैंक बहुत ज्यादा बुजुर्गों को क्रेडिट कार्ड जारी करने से हिचकते हैं.

कैश डिलीवरी ऐट डोरस्टेप

मौजूदा स्थितियों में कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों को खास सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इच्छुक होंगे. इन्हीं सुविधाओं में एक 'कैश डिलीवरी ऐट डोरस्टेप' है. इसमें घर बैठे कैश डिलीवरी या तो मुफ्त या मामूली फीस लेकर दी जाती है. यह सुविधा रवि के माता-पिता के लिए काफी उपयोगी साबित होगी. उन्हें जब पैसे की जरूरत हो, वे ऐसा कर सकते हैं. ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रवि अपने माता-पिता को घर में बहुत ज्यादा पैसा रखने से बचा सकते हैं. इनकी मदद से बुजुर्ग बिना अपनी सुरक्षा की चिंता किए पूरी आजादी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं.

जब आपस में भिड़ गए 2 बुजुर्ग

सोशल VIRAL

कमाल का एनर्जी लेवल

सोशल मीडिया पर हमेशा कोई न कोई वीडियो छाया रहता है. इनमें कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं, जिन पर लोगों को यकीन तक नहीं हो पाता है. वहीं, कुछ को देखकर लोगों का दिन बन जाता है. एक ऐसा ही मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसे देखने के बाद पहले तो आप हैरान होंगे, लेकिन आपको मजा भी आएगा. क्योंकि इस वीडियो में 2 बुजुर्गों में जिस तरह की एनर्जी दिख रही है, उसने अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं.

दंग रह गए लोग

आमतौर पर जिस उम्र में लोग ठीक से उठ-बैठ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, उस उम्र में 2 बुजुर्ग जबरदस्त फाइट करते नजर आ रहे हैं. बुजुर्गों का अंदाज देखकर एक पल के लिए लोग दंग रह गए और वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. इस वीडियो में, एक खेत में दो बुजुर्ग काफी एनर्जी में नजर आ रहे हैं. उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी से भी दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं. इसके बाद दोनों जिस तरह से एक-दूसरे पर टूटते हैं, उसने लोगों को हैरान कर दिया.

प्रोटीन से बढ़ेगी मांसपेशियों की ताकत

सबसे ज्यादा बुजुर्गों के खानपान का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन दिनों में मांसपेशियां, हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं. जिसके कारण खाने के साथ-साथ ऐसी चीजें देनी होती हैं जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो. एक दिन के आहार में रोजाना 3 बार समान मात्रा में प्रोटीन खाने से बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि हो सकती है. बहुत से बुजुर्ग प्रोटीन अक्सर दोपहर व रात के भोजन से प्राप्त करते हैं. नए शोध में सुझाया गया है कि नाश्ते में भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए. कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर स्टीफेन चेवलियर ने कहा, 'हमने देखा कि जिन लोगों ने नाश्ते में अपने प्रोटीन को शामिल किया व खाने के दौरान 3 बार प्रोटीन लेने में संतुलन बनाया, उनके मांसपेशियों में मजबूती दिखाई दी.' इसमें शोध दल ने प्रोटीन खपत की मात्रा और उनके वितरण की जांच की. यह जांच 67 साल व इससे ज्यादा आयु वाले लोगों पर की गई.

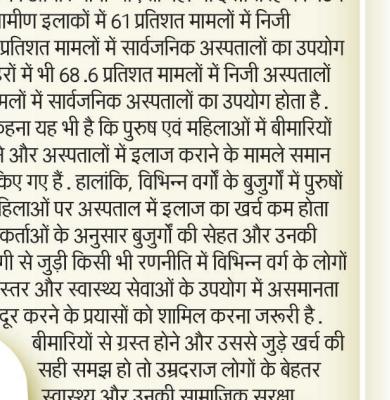

इसाबेल स्टेडमैन के कार ड्राइविंग के शौक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपना लाइसेंस बनवाने के लिए वे अब तक लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं. उनकी उम्र 47 साल है और वे पिछले 30 वर्षों से ड्राइविंग टेस्ट पास करने की कोशिश कर रही हैं. जब वह 17 साल की थीं, तब उन्होंने ड्राइविंग सीखने की शुरुआत की थी. इसाबेल एक सुपरमार्केट में काम करती हैं. वे कहती हैं - "मैं पिछले 30 वर्षों से ड्राइविंग सीख रही हूं, लेकिन अब भी जब मैं कार में दाखिल होती हूं तो ऐसा लगता है कि मैं कभी कार में बैठी ही नहीं हूं. यह मुझे डरा देने वाला है".

10 लाख रुपए हो चुके ख़र्च

30 वर्षों से दे रहीं ड्राइविंग टेस्ट

इसाबेल को ब्लैक आउट की समस्या है. वे खुद नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों होता है. कार चलाते ही वे अचानक टेंशन में आ जाती हैं. उन्हें ऐसा लगता है जैसे दिमाग अभी फट जाएगा और वे अपना होश खो बैठती हैं. वह परेशान होकर रोने लगती हैं और घर जाना चाहती हैं. इतना होने के बाद भी वे कार चलाना चाहती हैं ताकि अपनी बेटी को कार चलाकर यूनिवर्सिटी लेने जा सकें और दूर रहने वाले रिश्तेदारों से मिल सकें. वे चाहती हैं कि उनके दोनों बच्चे जल्दी ही ड्राइविंग टेस्ट पास कर लें. हालांकि उनके दोनों बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं. इसाबेल को उम्मीद है कि एक दिन वे ड्राइविंग लाइसेंस पाकर रहेंगी.

सुविधाओं के हकदार हैं सीनियर्स

■ देश में बुजुर्ग आबादी सम्मान के साथ नहीं रह रही है, खराब पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ रही है. ऐसे में राज्यों को बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की जरूरत है. इसके साथ अधिक वृद्धाश्रम भी बनाए जाएं ताकि उम्रदराज लोग वहां सम्मान के साथ रह सकें. उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए.

■ 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग अभी भी काम कर सकते हों, उन्हें रोजगार के वैकल्पिक मौके दिलाए जाएं. इससे बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी.

■ पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं के परिवार की तरफ से प्रताड़ित किए जाने की आशंका अधिक रहती है. उन्हें विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए.

■ इनकम टैक्स में छूट और बचत पर अधिक ब्याज दर भी सीनियर सिटिजंस के लिए बहुत जरूरी है. इससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा हासिल करने में मदद मिलती है. रेल और हवाई किराये में छूट देकर उन्हें घूमने-फिरने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे बुजुर्गों की ज़िंदगी खुशगवार बनेगी. उन्हें यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ भी मिलना चाहिए, जिसकी कुछ हद तक व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के जरिये की गई है.

■ अकेलेपन और डिप्रेशन के शिकार बुजुर्गों की मदद के लिए सोशल वर्कर्स हों, जो उनके यहां जाएं. बुजुर्गों को रोजमर्रा के नहाने, कसरत और खाने पकाने जैसे कामों में भी मदद की जरूरत है. इनमें भी सोशल वर्कर्स की भूमिका हो सकती है. हेल्पएज इंडिया जैसे कुछ NGO इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह मौजूदा जरूरतों को देखते हुए काफी नहीं है.

एक नज़र

चीन का मुसलमान कैसा होना चाहिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी हिदायत

एजेंसी

नई दिल्ली। चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन कई बार दुनियाभर में चर्चा में रहा है। हालांकि चीन ने कभी भी इस पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। इसी बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बताया कि चीन का मुसलमान कैसे होना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने प्रशासन को बकायदा आदेश दिया है कि वे इस्लाम को चीन की परंपराओं और समाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करें।

चार दिन के दौरे पर शिनजियांग पहुंचे जिनपिंग: दरअसल, चीन के शिनजियांग प्रदेश के दौरे पर पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह चीनी मुस्लिमों को लेकर कई बातें कही हैं। यह वही शिनजियांग है जहां उइगर मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग अपने चार दिन के दौरे पर शिनजियांग पहुंचे हैं। जिनपिंग ने यहां अपने अधिकारियों से कहा है कि इस्लाम को चीन के अनुकूल बनना चाहिए और समाजवादी ढांचे को अपनाना चाहिए।

चीन के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाने पर जोर दिया: जिनपिंग ने चीन के लिए मजबूत सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने समेत अलग-अलग जातीय समूहों के बीच लेन-देन, बातचीत और एकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस समुदाय को चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें अन्य समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। शी ने धार्मिक मामलों में शासन क्षमता में सुधार लाने और धर्मों के स्वस्थ विकास को साकार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मुस्लिमों को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाए जा रहे समाजवादी समाज के अनुकूल होना चाहिए। यह भी कहा कि धर्म को मानने वाले लोगों की सामान्य धार्मिक जरूरतों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उन्हें पार्टी और सरकार के करीब एकजुट होना चाहिए।

शिवसेना के नए नेता बने शिंदे

बागी गुट ने पुरानी कार्यकारिणी भंग की, लेकिन उद्धव को पार्टी प्रमुख के पद से नहीं हटाया

एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद अब पार्टी (शिवसेना) पर घमासान तेज हो गया है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने सोमवार को अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई।

शिंदे गुट ने इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुन लिया गया है। खास बात यह है कि शिवसेना ने पार्टी प्रमुख के पद को नहीं हटाया है। यानी उद्धव ठाकरे का पद जस का तस रखा गया है।

दीपक केसरकर को प्रवक्ता चुना गया: नई कार्यकारिणी में दीपक केसरकर को प्रवक्ता चुना गया है, जबकि रामदास कदम और आनंदराव अडसुल को नेता चुना गया है। यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शरद पोंकशे, तानाजी सावंत, विजय नाहटा, शिवाजीराव अधराव पाटिल को उपनेता चुना गया है।

उद्धव गुट ने दो नेताओं को पार्टी से निकाला: पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उद्धव ठाकरे गुट ने वरिष्ठ नेता रामदास कदम और पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल को शिवसेना से निकाल दिया है। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि शिंदे गुट की हुई मीटिंग में दोनों नेता शामिल हुए थे जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार: कभी कांग्रेस हाईकमान पर लगाया था टिकट बेचने का आरोप; राजस्थान समेत 4 राज्यों की राज्यपाल रहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित किया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में रविवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। 80 साल की अल्वा मूल रूप से कर्नाटक के मेंगलुरु की रहने वाली हैं। उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से होगा।

राजीव-नरसिम्हा की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं: मार्गरेट अल्वा राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। राजीव कैबिनेट में अल्वा संसदीय कार्य और युवा विभाग की मंत्री रहीं, जबकि राव की सरकार में पब्लिक और पेंशन विभाग की मंत्री रही हैं।

कांग्रेस हाईकमान पर लगाया था टिकट बेचने का आरोप: 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अल्वा ने कांग्रेस हाईकमान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस ने महासचिव पद से हटा दिया था। अल्वा उस वक्त महाराष्ट्र, मिजोरम और पंजाब-हरियाणा की प्रभारी थीं। हालांकि गांधी परिवार से नजदीकी रिश्ते होने की वजह से उन्हें उत्तराखंड में राज्यपाल बनाकर भेजा गया था।

शाहबानो केस और राजीव गांधी को लेकर किया था खुलासा: 2016 में अल्वा ने अपने बायोग्राफी करेज एंड कमिटमेंट में खुलासा किया था। उन्होंने लिखा- राजीव गांधी जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाने जा रहे थे, तब मैंने उन्हें मौलवियों के आगे नहीं झुकने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मेरा सुझाव मानने से इनकार कर दिया था।

गुजरात-राजस्थान समेत 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं: अल्वा गुजरात, राजस्थान, गोवा और उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वे उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। 2009 से 2012 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा राजस्थान में 2012 से 2014 तक राज्यपाल रहीं। इसी दौरान उन्हें गुजरात और गोवा का प्रभार भी मिला था।

धर्मांतरण बिल लाने पर BJP सरकार के ख़िलाफ़ मुखर रही थीं: पांच बार सांसद रहीं मार्गरेट अल्वा ने पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की धर्मांतरण विरोधी विधेयक के लिए जमकर आलोचना की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि 'मुझे अक्सर मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों में सीटों के लिए भाजपा सांसदों और विधायकों के कॉल आते हैं। अगर हम उनका धर्मांतरण करते हैं तो वे अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में क्यों भेजते हैं? उन्होंने कहा था- क्रिश्चियन पावर ने 200 साल तक भारत पर शासन किया। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच यहां थे। आज हम देश की जनसंख्या का मुश्किल से 3 प्रतिशत हैं। अगर हमने धर्मांतरण किया था तो हमें कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए था।

भाजपा उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा मुकाबला: अल्वा का मुकाबला भाजपा नीत एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा। धनखड़ वर्तमान में बंगाल के राज्यपाल हैं। 70 साल के जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे।

पुल से नर्मदा में गिरी बस, 13 शव निकाले

इंदौर-खरगोन के बीच भीषण हादसा, पुणे जा रही बस में 40 यात्री थे

एजेंसी

धार/धामनोद। मध्यप्रदेश के धार जिले में सोमवार सुबह इंदौर - खरगोन के बीच बड़ा हादसा हो गया। इंदौर से पुणे जा रही बस सुबह पौने दस बजे धामनोद में खलघाट के पास नर्मदा नदी में गिर गई। बस में महिलाओं-बच्चों समेत 40 यात्री सवार थे। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है।

बताया गया कि बस खलघाट में टू-लेन पुल पर किसी वाहन को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए हैं। इंदौर और धार से हृष्ठक्रस्न की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यह पुल पुराना बताया जा रहा है। बस महाराष्ट्र राज्य परिवहन की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को बचाव और राहत कार्य के आदेश दिए हैं।

सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की। बस हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र भेजेंगे। शिवराज ने उन्हें प्रशासन के प्रयासों से अवगत कराया। मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री कमल पटेल को घटनास्थल पर भेजने की जानकारी दी।

इंदौर से 80 किलोमीटर दूर हुआ हादसा: हादसा आगरा-मुंबई (AB रोड) हाईवे पर हुआ। यह रोड इंदौर से महाराष्ट्र को जोड़ता है। घटनास्थल इंदौर से 80 किलोमीटर दूर है। जिस संजय सेतु पुल से बस गिरी, वो दो जिलों- धार और खरगोन की सीमा पर बना है। पुल का आधा हिस्सा खलघाट (धार) और आधा हिस्सा खलटाका (खरगोन) में है। खरगोन से भी कलेक्टर और SP भी मौके पर पहुंचे हैं।

अब तक एक भी यात्री जीवित नहीं मिला

खलघाट टोल नाके की हाईवे एम्बुलेंस के ड्राइवर श्रीकृष्ण वर्मा ने बताया- मैं ड्यूटी पर था। सुबह 10.03 बजे कंट्रोल रूम से कॉल आया। सूचना मिली कि पुल से एक बस नर्मदा नदी में गिर गई है। सूचना मिलने के करीब 3 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गया था। बस नदी में गिरी हुई थी। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नदी से अब तक एक भी व्यक्ति जीवित या घायल नहीं निकाला जा सका है। बस को नदी से निकाल लिया गया है।

होटल मालिक बोला- चाय-नाश्ता करने रुके थे यात्री: बताया जाता है कि बस MH 40 N 9848 सुबह 9 से 9.15 बजे खलघाट से 12 किलोमीटर पहले दूधी बायपास किनारे एक होटल पर रुकी थी। होटल मालिक ने बताया कि यहां 12-15 यात्रियों ने चाय-नाश्ता किया। बाकी सवारी अंदर बैठी थी। अंदर कितनी सवारी यह तो पता नहीं, लेकिन बस में 30 से 35 सवारी होंगी।

यासीन मलिक पूर्व सीएम सईद की बेटी का किडनैपर

रूबिया ने कोर्ट में पहचाना, 32 साल पहले रिहाई के बदले 5 आतंकी छोड़ने पड़े थे

महबूबा मुफ्ती
जम्मू-कश्मीर की पूर्व CM

रूबिया सईद
महबूबा मुफ्ती की बहन

एजेंसी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने किया था। रूबिया ने शुक्रवार को CBI की विशेष अदालत के सामने गवाही में यासीन मलिक समेत 4 आतंकियों की पहचान की, जिन्होंने उनका अपहरण किया था। रूबिया पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बहन हैं। यह पहली बार है, जब रूबिया को इस मामले में पेश होने के लिए कहा गया था। वे फिलहाल तमिलनाडु में रहती हैं। रूबिया का अपहरण 8 दिसंबर 1989 को हुआ था। उनकी रिहाई के लिए 13 दिसंबर को सरकार को 5 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृहमंत्री थे। CBI ने 1990 की शुरुआत में इस केस की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

तस्वीरों के आधार पर हुई पहचान: रूबिया के वकील अनिल सेठी ने बताया कि वह CBI के सामने अपने पहले दिए गए बयान पर कायम हैं। उन्होंने CBI जांच के दौरान उपलब्ध कराई गई तस्वीरों के आधार पर यासीन मलिक और तीन अन्य की पहचान की। अपहरण के 31 साल से अधिक समय बाद मलिक और नौ अन्य के खिलाफ अदालत ने पिछले साल जनवरी में आरोप तय किए थे।

23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई: सेठी के मुताबिक सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त तय की गई है। अगली तारीख पर रूबिया भी मौजूद रहेंगी। यासीन मलिक ने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खुद को व्यक्तिगत तौर पर जम्मू ले जाने की मांग की है। हालांकि यासीन को जम्मू लाया जाएगा या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं मिली है।

अस्पताल से अपने घर लौट रही थीं रूबिया: रूबिया सईद के अपहरण को लेकर श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में 8 दिसंबर 1989 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

भारत में मंकीपॉक्स का पहला मामला

UAE से केरल लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव; केंद्र ने राज्यों को जारी किए निर्देश

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत में मंकीपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। मरीज तीन दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरत (UAE) से केरल के कोल्लम पहुंचा है। गुरुवार को केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मरीज में तेज बुखार और शरीर पर छाले जैसे लक्षण देखे गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल वह खतरे से बाहर है।

जॉर्ज ने बताया कि शख्स विदेश में मंकीपॉक्स के मरीज के संपर्क में था। वहीं, मरीज के संपर्क में आए उसके माता-पिता, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर समेत फ्लाइट में साथ आने वाले 11 यात्रियों की भी जांच की जाएगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी मंकीपॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया था। हालांकि बाद में उसकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई थी।

केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन: दुनिया में मंकीपॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर मंकीपॉक्स के खिलाफ सतर्कता बरतने और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है।

सरकार ने राज्यों को पॉइंट ऑफ एंट्री यानी यात्रियों के आने की जगहों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यहां निगरानी रखने वाली टीम से लेकर डॉक्टर्स, सभी तैनात रहेंगे। इसके अलावा, जिन भी लोगों में लक्षण पाए जाएंगे, उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को मंकीपॉक्स के लिए अलग से अस्पताल निर्धारित करने को कहा है। यहां बीमारी के दौरान मरीजों को आइसोलेट करने और उनके इलाज की सुविधाओं का बंदोबस्त किया जाएगा।

केरल में NEET देने गई छात्राओं से ब्रा उतरवाई

जांच में हुक से मेटल डिटेक्टर की बीप बजी तो हुआ एक्शन, FIR दर्ज

तिरुवनंतपुरम। केरल में कोल्लम जिले के एक एग्जाम सेंटर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET देने पहुंची छात्राओं से ब्रा उतरवा लिए गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा जांच के दौरान हुक के संपर्क में आने से मेटल डिटेक्टर की बीप बजी। इसके बाद सभी छात्राओं से ब्रा उतरवा लिए गए।

महिला कर्मचारी- बोली ब्रा नहीं निकाला तो एग्जाम नहीं दे पाओगी: घटना मार्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रविवार को हुई। लेकिन एक लड़की के पिता की ओर से FIR दर्ज कराए जाने के बाद मामला सामने आया है। छात्रा का कहना है कि उसने ब्रा निकालने से मना किया था। इस पर जांच कर रही महिला कर्मचारी ने कहा कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा।

महिला कर्मचारी ने कहा कि भविष्य जरूरी है या इनरवियर? बस इसे हटा दें और हमारा समय बर्बाद न करें। ऐसा कई छात्राओं के साथ हुआ। छात्रा ने बाद में ब्रा अपनी मां को दे दी ताकि उसे परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल सके। उसने खुद को कवर करने के लिए शॉल भी मांगा।

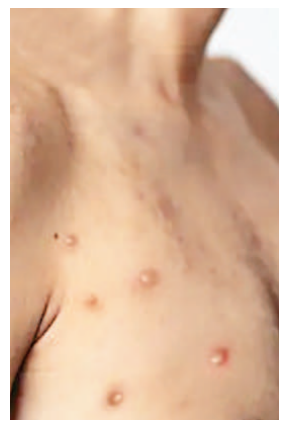

90% छात्राओं के इनरवियर निकलवाए: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अन्य लड़की को अपनी जींस उतारने के लिए कहा गया क्योंकि उसमें मेटल के बटन और जेब थीं। छात्राओं के अनुसार, जब वे परीक्षा देकर बाहर निकलीं तो उन्हें सारे अंडरगारमेंट्स डिब्बों में एकसाथ फेंके हुए मिले। शिकायत में यह भी कहा गया है कि एग्जाम सेंटर पर करीब 90% छात्राओं को अपने इनरवेयर निकालने पड़े।

इंस्टीट्यूट का इनकार, पुलिस ने की पुष्टि: इंस्टीट्यूट ने ऐसी घटना से इनकार किया है। वहीं, कोल्लम पुलिस चीफ केबी रवि ने केस दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है। पुलिस को लिखे शिकायती लेटर में पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने इनरवियर से भरा एक कमरा देखा था। एग्जाम सेंटर पर कई लड़कियां रो रही थीं और मानसिक तौर प्रताड़ित महसूस कर रही थीं।

प्रोटोकॉल में अंडरगारमेंट्स का जिक्र नहीं: दरअसल, परीक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से परीक्षा केंद्र में किसी भी छात्र-छात्रा को धातु की वस्तु या सामान पहनने की अनुमति नहीं है। इसे परीक्षा में धोखाधड़ी से बचने का उपाय बताया जा रहा है। एडवाइजरी में बेल्ट का जिक्र तो है, लेकिन ब्रा जैसे अंडरगारमेंट्स का जिक्र नहीं है।

केरल की उच्च शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई, मंत्री ने कहा- ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे

इस मामले पर केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने सोमवार को कहा कि परीक्षा किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं कराई है। जो हुआ वह गंभीर चूक का संकेत देता है। ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम एग्जाम सेंटर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से शिकायत करेंगे। NTA शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा कराती है।

hillviewsamachar@gmail.com

हिलव्यू समाचार

08

जयपुर, गुरुवार, 21 जुलाई, 2022

एक नज़र

आधारशिला फाउंडेशन ने 'उमंग स्कूल ' में किया सांस्कृतिक आयोजन और शिक्षा व कला की बाँटी सामग्री

जयपुर। सावन के महीने में आधारशिला फाउंडेशन द्वारा शरीर एवं मानसिक विकारों से ग्रस्त बच्चों के 'उमंग स्कूल' में बच्चों को स्टेशनरी, ड्राइंग शीट, ड्राइंग कलर्स एवं खाद्य प्रदार्थ इत्यादि सामान वितरित किया गया। फ़ाउंडेशन के सदस्य बच्चों के साथ रूबरू हुए, समय व्यतीत किया साथ ही एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया जिसको सुन बच्चे खुशी से झूम उठे। आधारशिला के फ़ाउंडर डॉ .शालिनी माथुर ने बताया कार्यक्रम में उपस्थित जयपुर की 40 समाज सेविकाओं का भी सम्मानित किया गया । इस कार्य में अन्ना अशोक, आशा अरोड़ा, नीलू जैन, उर्मिला न्याति, सीमा वालिया, मीनाक्षी चौधरी, रजनी श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, आभा सक्सेना, प्रियांशी डोगरा, प्रियंका गोयल , मीनू शर्मा , रेनू माथुर , पिंकी माथुर , ज्योति, पूनम खुराना , सुरेखा मित्तल , मंजू महेश्वरी , मोनीला माथुर , अंकिता, सरोज , आभा अरोड़ा , बबीता सोनी, माधुरी कुमार शांति भटनागर रजनी माथुर सुमन जोशी, विनय सोकिया, खुशबू शर्मा, इत्यादि ने सहयोग किया। मंच संचालन सीमा वालिया ने किया और छायाकार विनय सोनिया रहे।

जयपुर मेट्रो द्वारा रीट परीक्षार्थियों हेतु 22 से 25 जुलाई तक निशुल्क यात्रा

जयपुर। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर मेट्रो कुंजीलाल मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार राज्य में 23 व 24 जुलाई को आयोजित रीट परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों हेतु दिनांक 22 से 25 जुलाई 2022 तक जयपुर मेट्रो की यात्री सेवा निशुल्क रहेगी। मेट्रों में यात्रा हेतु परीक्षार्थियों को अपना परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाना होगा। यह मेट्रो सेवा प्रात : 5:10 से रात्रि 11 बजे तक अतिरिक्त फोटो के साथ उपलब्ध रहेगी।

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

JAIPUR METRO

नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन ने दी राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी

डीएलबी डायरेक्टर ह्रदेश शर्मा को ज्ञापन देते हुए राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष भागचंद श्रीमाल व सदस्यगण।

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष भागचंद श्रीमाल और अन्य पदाधिकारियों ने बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग निदेशक ह्रदेश कुमार शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन और मांग पत्र सौंपा। श्रीमाल ने बताया कि श्री गंगानगर में स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील कुमार शर्मा से ड्यूटी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की इसके बाद विभाग ने सुशील कुमार का निलंबन भी कर दिया इसके विरोध में श्रीगंगानगर जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 दिन से पेन डाउन और झाड़ू डाउन हड़ताल जारी की हुई है। भागचंद श्रीमाल ने आगे कहा कि अगर स्वायत्त शासन विभाग ने जल्द ही इस मामले का निस्तारण नहीं किया तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

राजस्थान में महंगी हुई बिजली: फ्यूल सरचार्ज वसूली के चक्कर में अगस्त-सितंबर का बिल आएगा ज़्यादा

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रेट से घरेलू, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिजली कंज्यूमर्स से वसूली होगी। इसका सीधा असर प्रदेश के करीब 1 करोड़ 30 लाख कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। साल 2021-22 की दूसरी तिमाही (जुलाई-अगस्त-सितम्बर 2021) की यह फ्यूल सरचार्ज वसूली आगामी अगस्त और सितम्बर 2022 के बिजली बिलों में की जाएगी। यही नहीं, पिछले एक साल का फ्यूल सरचार्ज तय होना बाकी है। इसलिए आगे बिजली के बिल बढ़कर आने तय हैं। तीनों बिजली कम्पनियां- JVVNL (जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड), JDVVNL (जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेज), AVVNL (अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेज) बढ़े हुए फ्यूल सरचार्ज की वसूली कंज्यूमर से करेंगी। एनर्जी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डिस्कॉम्स चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया- जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (RERC) ने फ्यूल सरचार्ज वसूली 24 पैसे प्रति यूनिट तय की है। बिजली उपभोक्ताओं पर आने वाले भार को देखते हुए राहत देने के लिए इस अमाउंट को दो बराबर किस्तों में अगस्त और सितम्बर, 2022 के बिजली बिलों में वसूलने का फैसला लिया गया है। फ्यूल सरचार्ज के कैलकुलेशन में शॉर्ट टर्म और एनर्जी एक्सचेंज से खरीदी पावर को शामिल नहीं किया जाता है। कृषि उपभोक्ताओं के बिजली कन्जम्पशन पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में उस अमाउंट को भरेगी। प्रदेश के 15.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का असर नहीं पड़ेगा।

350 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर 263 रुपए वसूली होगी: पिछले क्वार्टर के आधार पर कैलकुलेशन करते हुए मिडिल क्लास घर का उदाहरण लें, तो महीने में 350 यूनिट बिजली यूज होने पर उपभोक्ता को करीब 263 रुपए तीन महीने के बिल पर फ्यूल सरचार्ज के चुकाने होंगे। ज्यादा बिजली कन्ज्यूम होने पर उसी रेश्यो में यह अमाउंट बढ़ता जाएगा। अनुमान के मुताबिक, अकेला जयपुर डिस्कॉम ही 250 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली करता है। तीनों डिस्कॉम्स 550 से 650 करोड़ रुपए तक उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलते हैं। **साल 2012-13 से हर 3 महीने के आधार पर वसूली जारी:** यह फ्यूल सरचार्ज साल 2012-2013 से रेगुलर 3 महीने के आधार पर बिलों के जरिए वसूल किया जा रहा है। बिजली डिस्कॉम के प्रपोजल के बाद आने वाले महीनों में RERC जो फ्यूल सरचार्ज तय करेगा, उसी आधार पर ज्यादा या कम वसूली होगी।

क्या होता है फ्यूल सरचार्ज ?

डिस्कॉम बिजली सप्लाई के लिए अलग-अलग सोर्सेज से ऋश्चऋष्ट की ओर से तय फिक्स्ड और वैरिएबल कॉस्ट की रेट पर बिजली खरीदता है। कमीशन की ओर से तय रेट्स पर बिजली कन्ज्यूमर्स की कैटेगरी के हिसाब से चार्ज की वसूली की जाती है। फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी, टैक्स और सरचार्ज की रेट में बदलाव, रेल और मालभाड़े में बढ़ोतरी के कारण बिजली प्रोडक्शन की रेट में बदलाव होता है। अलग-अलग बिजली प्रोडक्शन सेंटर्स या पावर प्लांट से वास्तविक प्रोडक्शन लागत के मुताबिक बिजली की वैरिएबल कॉस्ट बाद में मिलती है। इसकी वसूली बिजली उपभोक्ताओं से बाद में की जाती है।

बोर्ड-निगमों के अध्यक्षों की सैलरी 40 हजार बढ़ी

राज्य मंत्री का दर्जा वाले 26 चेयरमैन का वेतन-भत्ता 1 लाख 17 हजार रुपए हुआ

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान के अलग-अलग बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए बने अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के वेतन भत्तों में 40 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के दर्जा वाले बोर्ड और निगम अध्यक्षों के वेतन भत्ते 52 फीसदी तक बढ़े हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले बीजेपी राज के दौरान 7 दिसंबर 2017 को बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते बढ़ाए गए थे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाले अध्यक्षों का वेतन 45000 से बढ़ाकर 65000 रुपए प्रतिमाह और सत्कार भत्ता दर्जा 34000 से बढ़ाकर 55000 रुपए कर दिया है। जो पहले कुल 79 हजार रुपए थे, अब बढ़कर हर महीने 1 लाख 20 हजार रुपए हो गए हैं।

राज्य मंत्री का दर्जा वाले बोर्ड निगमों के अध्यक्षों का वेतन भी बढ़ा

राज्य मंत्री का दर्जा वाले बोर्ड निगमों के अध्यक्षों का वेतन 42000 से बढ़ाकर 62000 रुपए और सत्कार भत्ता 34000 से बढ़ाकर 55000 रुपए किया है। जो पहले कुल 76000 रुपए मिलते थे, अब 1 लाख 17 हजार रुपए मिलेंगे। प्रदेश में अभी 26 बोर्ड-निगमों के 26 अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, जबकि 3 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। बीसूका (बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति) उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान, खादी, ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा और राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है।

इन 26 नेताओं को मिला हुआ है राज्य मंत्री का दर्जा

मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबैर खान, बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर, लघु उद्योग विकास निगम अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज, विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली, बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप चौधरी, वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी अध्यक्ष रामसिंह राव, घुमंतू कल्याण बोर्ड अध्यक्ष उर्मिला योगी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड अध्यक्ष अनिल शर्मा, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर, ओबीसी वित्त विकास निगम अध्यक्ष पवन गोदारा, केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा, विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा, आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत, भूदान यज्ञ बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा, एससी वित्त विकास बोर्ड अध्यक्ष शंकर यादव, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष केसी विश्नोई, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत, स्वैच्छिक विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह।

आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव

केजरीवाल मॉडल पर होगी इलेक्शन फाइट, सभी ग्राम पंचायत-वार्ड्स में सामाजिक-धार्मिक-जातिगत सर्वे होगा

हिलव्यू समाचार

जयपुर। आम आदमी पार्टी राजस्थान में 2023 में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव दिल्ली और पंजाब की आप पार्टी की सरकार के कामों और केजरीवाल मॉडल को दिखाकर लड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल खुद राजस्थान में चुनावी सभाओं की शुरुआत जल्द करने जा रहे हैं। राजस्थान में ष्ट्रू फेस प्रदेश का ही होगा। पार्टी ने प्रदेश में संगठन का स्ट्रक्चर बनाने का काम तेज कर दिया है। साथ ही मेंबरशिप ड्राइव तेजी से बढ़ाने के लिए फोन पर मिस्ड कॉल से सदस्य बनाना भी शुरु कर दिया है। जिसके लिए 80-80-80-9064 नम्बर जारी किया है।

पूरे प्रदेश में चुनावी सर्वे शुरू कर रही आप: आम के पंजाब से राज्यसभा सांसद और हिमाचल,गुजरात प्रभारी संदीप पाठक ने बताया आप पार्टी पूरे प्रदेश में चुनावी सर्वे शुरू कर रही है। जिसकी शुरुआत पंचायत और वार्ड सम्पर्क अभियान से हो रही है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत प्रभावशाली व्यक्तियों का सर्वे करवाकर उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। पार्टी टिकट सर्वे के बेसिस पर ही देती है। इसलिए पंजाब की तरह राजस्थान में भी सर्वे करवाया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के जीतने के अच्छे चांस होंगे और अच्छी छवि होगी, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। महीने-दो महीने में बेसिक सर्वे शुरु हो जाएंगे। चुनाव के नजदीक कैंडिडेट्स का सर्वे होगा। जल्द ही अरविन्द केजरीवाल की बड़ी सभा भी जयपुर में होगी। उसकी डेट अभी तय नहीं हुई है।

पाठक ने कहा- सारे स्टेट अलग होते हैं। वहां चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अलग होती है। सभी राज्यों में जनता और उनकी बेसिक समस्याएं एक जैसी हैं। हमें किसी चाणक्य की जरूरत नहीं है। वो मुद्दे उठाने हैं, जिनसे जनता परेशान है। फिर जनता खुद सिर आंखों पर उठाएगी। गुड गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा जीरो टोलरेंस है। दिल्ली और पंजाब में हम मंत्री को बर्खास्त करके इसका उदाहरण पेश कर चुके हैं।

अगले दो महीने में सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे

प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा भी पाठक के साथ जयपुर के पिंकसिटी प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। मिश्रा ने कहा हमने राजस्थान में पहले सम्भाग यात्रा निकाली। 800 मीटिंग का लक्ष्य रखकर 692 मीटिंग पूरी कर लीं। अब हम ग्राम पंचायत अभियान शुरू करने जा रहे हैं। टारगेट सारी ग्राम पंचायत और वार्डों में पहुंचना है। लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रहा है। जनता में एनर्जी बहुत है। वह बदलाव चाह रही है। जैसे-जैसे हम सड़क पर दिखेंगे जनता का जुड़ाव होता जाएगा। सहयोग के हिसाब से हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगले दो महीने में सारी पंचायतों में पहुंच जाएंगे।

करप्शन, एजुकेशन-हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस मुद्दे

संदीप पाठक ने कहा- पार्टी संगठन बनाने का काम भी शुरू हो गया है। हम गांव,पंचायत लेवल पर संगठन को मजबूत करेंगे। फिर सर्कल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी, स्टेट यूनिट और प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, बेरोजगारी की समस्या, गवर्नमेंस, करप्शन के मुद्दे मुख्य हैं। कांग्रेस-बीजेपी की सरकार आने पर कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा जबरदस्त गठजोड़ दोनों पार्टियों का बना हुआ है कि छोटे-मोटे दूसरे लोगखड़े होते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। राजस्थान में दोनों पार्टियों का बारी-बारी से यह खो-खो का खेल चल रहा है, इससे जनता त्रस्त है। जनता को अभी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चीजों से मतलब नहीं है।

राजस्थान में अवैध खनन से दुखी संत का आत्मदाह

80% झुलसे बाबा विजय दास, 551 दिन से चल रहा आंदोलन ख़त्म

हिलव्यू समाचार

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के पसोपा गांव में संत बाबा विजय दास ने अवैध खनन के विरोध में खुद को आग लगा ली। वे साधु-संतों के साथ पिछले 551 दिन से आंदोलन कर रहे थे। आग लगाने के बाद बाबा राधे-राधे कहते हुए दौड़ने लगे। पुलिसकर्मियों ने कंबल डालकर आग बुझाई, तब तक वे करीब 80 फीसदी जल चुके थे। बाबा को भरतपुर के राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, शाम 4.40 बजे उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। 7.15 बजे उन्हें गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल भर्ती कराया गया। बाबा के आत्मदाह के बाद राजस्थान के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया बैकफुट पर आ गए। मंत्री ने कहा कि संत जिन खानों को बंद करने की मांग कर रहे हैं, वे लीगल हैं। फिर भी उनकी लीज शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा।

डेढ़ साल बाद हुआ धरना खत्म: अवैध खनन के खिलाफ साधु संत करीब डेढ़ साल से धरना दे रहे थे। बुधवार शाम 5.45 बजे पसोपा में मान मंदिर सेवा संस्थान बरसाना के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया। मंत्री ने 15 दिन में कनकांचल व आदिबद्री को वनक्षेत्र घोषित करने व 2 महीने में इन क्षेत्रों में चल रही सभी लीज को शिफ्ट करने का आश्वासन दिया, इसके बाद धरना खत्म कर दिया गया।

संत ने टावर पर 33 घंटे धरना दिया: सहमति बनने से पहले बुधवार को आंदोलन से जुड़े एक और संत बाबा नारायण दास 33 घंटे से टावर पर चढ़कर बैठे थे, वे दोपहर में बाबा विजयदास के आत्मदाह के प्रयास के बाद दोपहर 1.10 बजे टावर से उतर आए। नारायण दास मंगलवार सुबह 6 बजे से मोबाइल टावर पर चढ़े थे। वे बरसाना के रहने वाले हैं। आंदोलन को देखते हुए कमिश्नर सांवरमल वर्मा ने भरतपुर के पांच कस्बों में इंटरनेट बंद कर दिया था।

क्यों आंदोलन कर रहे थे साधु-संत?: राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग, कामां तहसील का इलाका 84 कोस परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। साधु-संतों का कहना है कि यह धार्मिक आस्था से जुड़ी जगह है, यहां हिंदू धर्म के लोग परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहां वैध और अवैध, दोनों तरह के खनन बंद होने चाहिए। इसी मांग को लेकर वे 551 दिनों से आंदोलन कर रहे थे।

संत इस जगह चारों धाम मानते हैं: साधु-संतों का दावा है कि कनकांचल और आदि बद्री पर्वत धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं। आदि में भगवान बद्री के दर्शन होते हैं, जबकि कनकांचल पर्वत में कई पौराणिक अवशेष हैं। इनकी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। इस जगह पर चारों धाम हैं।

सरकार की रोक के बाद भी चल रहा खनन: राजस्थान सरकार ने 27 जनवरी 2005 को आदेश निकाला था कि

खान मंत्री प्रमोद जैन भाया धार्मिक आस्था के प्रतीक माने जाते रहे है। ऐसे में संतों की पीड़ा से कैसे अछूते रह गए।

मंत्री बोले- खनन करने वाले रॉयल्टी दे रहे: संत के आत्मदाह के बाद खनन मंत्री ने कहा- पहाड़ी के आसपास 55-60 लीज दे रखी हैं। वे सब लीगल माइनिंग कर रहे हैं और उनके पास एनवायर्नमेंटल क्लियरेंस भी है। संत चाहते हैं कि वहां खनन बंद करके उस इलाके को वन क्षेत्र घोषित किया जाए।

भाया ने कहा कि इस मामले में CM की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई है। वे नियमानुसार खनन कर रहे हैं, रॉयल्टी दे रहे हैं। उन खानों की लीज कैंसिल करके दूसरी जगह लीज देने पर विचार करेंगे।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, एवं मुद्रक **शालिनी श्रीवास्तव के लिए** अम्बर ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड, डी.एल. टॉवर, 3-ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र, जेएलएन मार्ग, जयपुर में मुद्रित एवं प्लॉट नंबर C-2,अर्शिया रेजिडेंसी, फ्लैट नंबर 201,आदर्श नगर,राजा पार्क जयपुर-302004 (राजस्थान) से प्रकाशित।
संपादक : शालिनी श्रीवास्तव, सह-संपादक: हरीश श्रीवास्तव (छबड़ा बारां) मो.: 9460678701, 7976561127 (21 जून 2014 से निरन्तर प्रकाशित) **hillviewsamachar@gmail.com** (राजस्थान सरकार से विज्ञापन हेतु स्वीकृत)